JOTI JOURNAL
SUBJECT-INDEX
FEBRUARY-DECEMBER - 2020

Editorial		1
Editorial		27
Editorial		59
Editorial		101
Editorial		147
Editorial		181

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1.	Hon'ble Shri Justice Ajay Kumar Mittal, Chief Justice of Madhya Pradesh, demits office.	152
2.	Obituary	108
3.	Obituary	186
4.	Photographs	3
5.	Photographs	29
6.	Photographs	61
7.	Photographs	103
8.	Photographs	149
9.	Photographs	183
10.	Address of Hon'ble the Acting Chief Justice	189
11.	Automatic vacation of stay orders in six months: Import of Judgment in Asian Resurfacing	208
12.	Bar of subsequent suit in under Order 2 Rule 2 CPC	196
13.	Cognizance and Trial of Offences registered for violation of Prohibitory Orders issued to enforce Lockdown	71
14.	Contradiction and Omission: Nature and Mode of proof in Criminal Trials	50
15.	Determination of compensation against Medical Expenses	170
16.	Exercise of Jurisdiction during Investigation vis-a-vis on filing of charge-sheet	191
17.	Gandhian Philosophy of Justice and ADR Methods	153
18.	Interim Custody of Property in Forest Offences	89
19.	Judicial Ethics, Norms and Behaviour	33
20.	Jurisdictional Issues of Family Courts	109
21.	Law relating to admissibility of Electronic Records with reference to ***Arjun Panditrao Khotkar, (2020) 7 SCC 1***.	161

22. Limitation for cognizance of offences under M.P. Excise Act 211
23. Production of Child when Principal Magistrate and Members of J.J. Board are not available 135
24. Ruminations of a Referral Judge 119
25. Sale Transactions: Effect of Benami Prohibition Law (with reference to the amendments incorporated by the Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act, 2016) 156
26. Tips for Good Judging 11
27. Traits of a good Judge 16
28. Trial of offences under special law and/or under general law 18
29. Types & Quantification of Loss of Consortium 123
30. अपराधों का शमन : कतिपय मार्गदर्शी विधिक सिद्धान्त 202
31. पदार्थ की मात्रा और शुद्धता का आनुपातिक संबंध संदर्भ : स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 65
32. पारस्परिक सम्मति से हिन्दू विवाह–विच्छेद : विधिक अपेक्षाएँ 174
33. रिसीवर की नियुक्ति : मार्गदर्शी विधिक सिद्धांत 127
34. विधिक समस्याएँ एवं समाधान 97, 144, 177 & 217

1. क्या पुलिस अभिरक्षा में निरोध का आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय है और क्या अभियुक्त को निरोध में भेजे जाने से प्रथम पन्द्रह दिवस की अवधि के पश्चात् भी पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पुलिस निरोध में प्राधिकृत किया जा सकता है?
2. क्या दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील का निराकरण गुण–दोष पर किया जा सकता है तथा दोषमुक्ति के विरूद्ध की गई अपील में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रक्रिया क्या होगी?
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 3/2020 में दिये आदेश दिनांक 23.03.2020 तथा 06.05.2020 का धारा 167 (2) द.प्र.सं. के अन्तर्गत निरोध की अवधि की गणना पर क्या प्रभाव होगा?
4. मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर के मामले में यदि मृतक की आयु न्यायदृष्टांत ***सरला वर्मा विरूद्ध दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन*** में दी गई तालिका के निरंतर दो आयु वर्ग के मध्य की हो, जैसे – 40 से 45 वर्ष आयु वर्ग और 46 से 50 वर्ष आयु वर्ग के मध्य अर्थात 45 वर्ष से अधिक किन्तु 46 वर्ष से कम है तब ऐसी दशा में गुणांक किस आयु वर्ग के आधार पर प्रयोज्य होगा?

5. किसी गिरफ्तार अभियुक्त जिसे धारा 167 दं.प्र.सं. के अतंर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा निरोध में भेजा गया है, को और आगे निरोध में रखे जाने के लिए अन्वेषण अभिकरण यथा पुलिस आदि की ओर से कोई आवेदन पत्र व केस डायरी प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में भी क्या अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा और आगे निरोध में प्राधिकृत किया जा सकता है?

6. क्या धारा 439 द.प्र.सं. के अधीन जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

7. क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध अजमानतीय है?

8. क्या एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी, जो स्वयं परिवादी हो अर्थात् जिसने स्वयं ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की हो, द्वारा किए जाने से अन्वेषण और विचारण दूषित होगा और इस आधार पर अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी होगा?

9. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10 (सहपठित नियम 10–क) के अधीन लौटाये गये वाद पत्रों को निर्दिष्ट सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे पश्चात्वर्ती न्यायालय में विचारण की समुचित प्रक्रिया क्या होगी?

10. जब किसी अभियुक्त को क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तार कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है तब धारा 167 दं.प्र.सं. के अंतर्गत 60/90 दिन की गणना निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से होगी या क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से?

11. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की साक्ष्य में ग्राह्यता संबंधी अद्यतन विधि क्या है?

12. क्या धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं?

13. क्या एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत उल्लेखित सभी अपराध अजमानतीय प्रकृति के है?

14. क्या धारा 37 के अर्थों में आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध जमानतीय हैं?

15. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 में 'न्यायालय' तथा 'सिविल न्यायालय' से क्या तात्पर्य है?

16. क्या ऐसा व्यक्ति अभियोजन साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है जिसका अनुसंधान के समय विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन ही नहीं लिया गया है?

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Section 12 (1) (b) – Eviction of tenant on the ground of sub-letting – Proof of sub-tenancy.		
धारा 12 (1) (ख) – उप–किराएदारी के आधार पर किराएदार का निष्कासन – उप–किराएदारी का साबित किया जाना।	**1**	**1**
Section 12 (1) (b) – Eviction of tenant – Sub-tenancy – Burden of proof.		
धारा 12 (1) (ख) – किराएदार का निष्कासन – उप–किरायेदारी – सबूत का भार।	**178**	**247**
ADOPTION REGULATIONS, 2017		
दत्तकग्रहण विनियमन, 2017		
Regulations 21 and 41 – See Sections 58 and 59 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.		
विनियमन 21 एवं 41 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 58 एवं 59।	**102***	**142**
APPRECIATION OF EVIDENCE:		
साक्ष्य का मूल्यांकनः		
– Appreciation of evidence of eye witness.		
– चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**27**	**37**
– See Section 45 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45।	**10 (ii) & (iii)**	**25**
– See Sections 498-A and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 498–क एवं 302।	**47**	**61**
– When separation of truth from the falsehood is not feasible.		
– जब सत्य को असत्य से अलग करना असाध्य हो।	**28 (i)**	**38**
– Statement of Witnesses – Appreciation of – Evidence of witnesses has to be read as a whole – Words and sentences cannot be truncated and read in isolation.		
– साक्षियों के कथनों का मूल्यांकन – साक्षियों की साक्ष्य पूर्णता में पढ़ी जानी चाहिए – शब्दों और वाक्यों को अलग कर विलगता में नहीं पढ़ा जा सकता है।	**315 (i)**	**435**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996

Sections 2 (1) (e) and 20 – Arbitration – "Venue" and "Seat" – Meaning of.

धाराएं 2 (1) (ङ) एवं 20 – माध्यस्थम् – ''स्थान'' एवं ''पीठ''– तात्पर्य। **228** **325**

Sections 2 (1) (f) and 11(6) – Jurisdiction for arbitration – Where parties have chosen Hong Kong as the place of arbitration to be administered in Hong Kong.

धाराएं 2 (1) (च) एवं 11(6) – मध्यस्थता के लिए क्षेत्राधिकार – जहां पक्षकारों द्वारा हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता के लिए हांगकांग का मध्यस्थता के स्थान के रूप में चयन किया गया हो। **278** **385**

Sections 9, 20, 34 and 42 – Jurisdiction of Civil Court – Application for setting aside an arbitral award.

धाराएं 9, 20, 34 एवं 42 – सिविल न्यायालय की अधिकारिता – एक माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन। **229** **326**

Section 19 r/w/s 34 – (i) The rules of procedure to be followed by an Arbitral Tribunal are flexible and can be agreed upon by the parties.

(ii) Award can be challenged on the basis of non-compliance of agreed procedure.

धारा 19 सहपठित धारा 34 – (i) एक माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया लचीली है और पक्षकारों की सहमति से निर्धारित हो सकती है।

(ii) करार की गई प्रक्रिया का अनुपालन मध्यस्थ द्वारा नहीं करने के आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दी जा सकती है। **179** **248**

Sections 34 and 36 – Execution petition of arbitral award may be instituted after disposal of application u/s 34.

धाराएं 34 एवं 36 – माध्यस्थम् पंचाट के निष्पादन की याचिका, धारा 34 के अधीन आवेदन के निराकरण के पश्चात् संस्थित की जा सकती है। **118** **159**

Sections 34 and 37 – Arbitrability of dispute.

धाराएं 34 एवं 37 – मध्यस्थता योग्य विवाद। **61*** **85**

Sections 34 and 37 – Setting aside of arbitral award on the ground of "patent illegality".

धाराएं 34 एवं 37 – माध्यस्थम् अधिनिर्णय को ''प्रत्यक्ष अवैधानिकता'' के आधार पर अपास्त किया जाना। **279** **386**

BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) ACT, 1988
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988

Sections 3 and 4 – Proof of transaction to be benami.

धाराएं 3 एवं 4 – संव्यवहार के बेनामी होने को प्रमाणित किया जाना। **230** **328**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS ACT, 1960 (M.P.)		
कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (म.प्र.)		
Sections 7, 11, 41, 42 and 46 – Whether Civil Court has jurisdiction to decide a suit challenging order of surplus land of the Competent Authority under the Act?		
धाराएं 7, 11, 41, 42 एवं 46 – क्या सिविल न्यायालय, अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अधिशेष भूमि संबंधी आदेश को आक्षेपित करने वाले दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखता है?	**2***	**2**
CIVIL PRACTICE:		
सिविल प्रथाः		
– Court fee has to be paid in accordance with the claim made in the cross-objection.		
– न्यायालय शुल्क, प्रत्याक्षेप में किये गये दावे के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।	**231**	**328**
– Question of law, meaning of – Stage at which it may be considered?		
– विधि का प्रश्न, तात्पर्य – किस प्रक्रम पर परीक्षित किया जा सकता है।	**180**	**249**
– Reasons must be assigned while passing any order and legal questions arising in that case must be properly examined by the Appellate Court.		
– किसी भी आदेश को पारित करते समय कारण अवश्य उल्लेखित किए जाने चाहिए एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा उस मामले में उत्पन्न विधिक प्रश्नों का उचित तौर पर परीक्षण किया जाना चाहिए।	**119**	**160**
– See Order 23 Rule 3A, Order 41 Rules 1A and 22 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 23 नियम 3क, आदेश 41 नियम 1क एवं 22।	**10**	**13**
– See Section 5 of the Limitation Act, 1963.		
– देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।	**48**	**63**
– See Sections 5 and 108 of the Transfer of Property Act, 1882.		
– देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 5 एवं 108।	**277**	**381**
– See Sections 34, 38 and 39 of the Specific Relief Act, 1963.		
– देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 34, 38 एवं 39।	**328**	**452**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Section 9 – Exclusion of the jurisdiction of Civil Court is not to be readily inferred.

धारा 9 – सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन आसानी से अनुमानित नहीं किया जाना चाहिए। **120** **160**

Section 9 – Bar to jurisdiction of Civil Court – After incorporation of new Companies Act, 2013.

धारा 9 – नये कंपनी अधिनियम, 2013 के निगमित होने के पश्चात् सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। **290** **400**

Section 11 – Applicability of *res judicata* where earlier petition dismissed under Order 7 Rule 11.

धारा 11 – पूर्व न्याय की प्रयोज्यता जब पूर्व याचिका आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के अंतर्गत नामंजूर की गई हो। **280*** **387**

Section 11 and Order 1 Rule 10 – (i) Application for same relief which was denied earlier by the Court can be filed at later stage again, if fresh cause of action arises.

(ii) Impleadment of parties – Where a transferee *pendente lite* acquires any substantial interest in property.

धारा 11 एवं आदेश 1 नियम 10 – (i) यदि कोई नया वाद कारण उत्पन्न हो गया हो तब उसी अनुतोष हेतु, जिसे पूर्व में न्यायालय ने प्रदान करने से मना कर दिया था, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) पक्षकारों का जोड़ा जाना – जहां एक वादकालीन अंतरिती संपत्ति में कोई तात्विक अधिकार अर्जित कर लेता है। **121** **161**

Section 11 and Order 7 Rule 11(d) – Rejection of plaint – Plaintiff neither valued suit property nor paid proper court fees on plaint – Plaint liable to be rejected.

Rejection of plaint – Suit for cancellation of sale deed, possession and permanent injunction – Title over suit property already decided in earlier litigation between parties – Suit is barred by principle of *res judicata.*

धारा 11 एवं आदेश 7 नियम 11(घ) – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादी ने न तो वादग्रस्त संपत्ति का उचित मूल्यांकन किया और ना ही वादपत्र पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया – वादपत्र नामंजूर किये जाने योग्य है।

वादपत्र का नामंजूर किया जाना – विक्रय विलेख के निरस्तीकरण, आधिपत्य प्राप्ति और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद – पक्षकारों के बीच पूर्व मुकदमेबाजी में वादोक्त संपत्ति पर स्वत्व पूर्व से ही निराकृत – प्रांगन्याय के सिद्धांत द्वारा वाद वर्जित है। **3* (ii) & (iii)** **2**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 47 – Whether execution of sale deed could be directed in execution of award fixing price of land? Held, No.

धारा 47 – क्या भूमि का मूल्य तय करने संबंधी अधिनिर्णय के निष्पादन में विक्रयपत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं। **281*** **387**

Section 89 (2) (d) – After successful mediation, a compromise must be affected by the court after following prescribed procedure and any order passed by mediator cannot be executed by the execution court.

धारा 89 (2)(घ) – सफल मध्यस्थता के पश्चात् न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए राजीनामा प्रभावशील करना चाहिए। मध्यस्थ द्वारा पारित कोई आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है। **282** **388**

Section 96, Order 23 Rules 3 and 3-A and Order 43 Rule 1-A – Remedy against Compromise decree.

धारा 96, आदेश 23 नियम 3 एवं 3–क तथा आदेश 43 नियम 1–क – समझौता आज्ञप्ति के विरुद्ध उपचार। **283** **388**

Section 96 and Order 41 Rule 22 – Appeal – Without filing a cross-objection, even an issue or any finding decided against the respondent can be assailed before the Appellate Court at the time of final hearing.

धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 22 – अपील – प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत कोई वाद प्रश्न या निष्कर्ष अपीलीय न्यायालय के समक्ष अंतिम सुनवाई के समय प्रत्याक्षेप प्रस्तुत किये बिना भी आक्षेपित किया जा सकता है। **232 (i)** **329**

Section 96 and Order 41 Rule 23 – Appeal – Whether an appeal admitted for final hearing without any objection as to delay may be rejected being barred by limitation without giving an opportunity to the appellant?

धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 23 – अपील – क्या अपील को विलंब की किसी आपत्ति के बिना अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिए जाने के बाद अपीलार्थी को कोई अवसर दिए बिना परिसीमा काल के वर्जन के आधार पर खारिज किया जा सकता है? **62** **85**

Section 96 and Order 41 Rule 31 – Appeal – Duties of appellate court.

धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 31 – अपील – अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य। **233*** **330**

Section 96 (2) and Order 9 Rule 13 – *Ex-parte* decree – Appeal filed after dismissal of application under Order 9 Rule 13 – Maintainability of.

धारा 96 (2) एवं आदेश 9 नियम 13 – एकपक्षीय आज्ञप्ति – आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन खारिज होने के उपरांत अपील प्रस्तुत की गई – पोषणीयता। **181** **249**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 149 – (i) Effect of permission to make up deficiency in court fees. (ii) Enforcement of agreement to sell – Proper form of relief is suit for specific performance and not mandatory injunction.		
धारा 149 – (i) न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा करने की अनुमति का प्रभाव। (ii) विक्रय की संविदा का प्रवर्तन – सहायता प्राप्त करने का उचित प्रकार विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद हैं ना कि आज्ञापक व्यादेश का।	**234**	**330**
Section 151 – Consolidation of suits.		
धारा 151 – वादों का समेकन।	**235***	**333**
Section 151 and Order 21 Rule 89 – When auction-sale can be set aside?		
धारा 151 एवं आदेश 21 नियम 89 – नीलामी–विक्रय को कब अपास्त किया जा सकता है?	**284***	**392**
Sections 151 and 152 – (i) Order rejecting an application for correction in the decree preferred u/s 151 and 152, cannot be held to be an interlocutory order. (ii) Correction of accidental slip or omission in judgment.		
धाराएं 151 एवं 152 – (i) धारा 151 और 152 के अंतर्गत आज्ञप्ति में शुद्धि के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश अंतर्वर्ती आदेश अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। (ii) निर्णय में आकस्मिक चूक या लोप का सुधार।	**4***	**3**
Order 1 Rule 10 – Necessary or proper party – In a suit for specific performance.		
आदेश 1 नियम 10 – विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद में आवश्यक या उचित पक्षकार।	**285**	**393**
Order 1 Rule 10 – Impleadment of third party or stranger to contract in a suit for specific performance of contract.		
आदेश 1 नियम 10 – तृतीय पक्षकार या संविदा में पर–व्यक्ति का संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिये वाद में संयोजन।	**5**	**4**
Order 2 Rule 2 (3) – Bar to second suit – Plaintiff filed a suit for declaration of possession and permanent injunction against defendant – Suit dismissed in default – Subsequent suit filed for specific performance of contract against defendant is barred under Order 2 Rule 2 (3).		
आदेश 2 नियम 2 (3) – द्वितीय वाद का वर्जन – वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जे की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया – वाद व्यतिक्रम के कारण खारिज किया गया – तदनन्दर प्रतिवादी के विरूद्ध संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत वाद आदेश 2 नियम 2 (3) द्वारा वर्जित है।	**182***	**251**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Order 3 Rules 1 and 2 – Scope of evidence by Power of attorney holder and right of Principal to enter into the witness box.

आदेश 3 नियम 1 एवं 2 – मुख्तारनामा धारक की साक्ष्य का विस्तार एवं मूल स्वामी का साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने का अधिकार। **122** **165**

Order 6 Rule 17 – Amendment – Plea of forgery in any document cannot be examined at the stage of amendment in pleadings as it is a matter of evidence.

आदेश 6 नियम 17 – संशोधन – किसी दस्तावेज में कूटरचना का अभिवाक् अभिवचनों में संशोधन की अवस्था में परीक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। **236** **333**

Order 6 Rule 17 – Amendment in plaint – Where the relief claimed by the proposed amendment is already existing in plaint in substance.

आदेश 6 नियम 17 – वादपत्र में संशोधन – जहां प्रस्तावित संशोधन द्वारा वांछित अनुतोष पूर्व से ही वादपत्र में किसी अन्य रूप में सारतः विद्यमान है। **123** **166**

Order 6 Rule 17 – Amendment of pleadings – At appellate stage – To incorporate plea of readiness and willingness.

आदेश 6 नियम 17 – अभिवचनों का संशोधन – अपील के स्तर पर – तत्पर और इच्छुक होने के अभिवचन के समावेश हेतु। **112** **152**

Order 6 Rule 17 – When new parties are added and they file their written statements with counter-claim then on the basis of such subsequent development, the plaintiff should also be allowed to amend the plaint.

आदेश 6 नियम 17 – जब नये पक्षकार जोड़े गये हैं और वे लिखित कथन के साथ अपना प्रतिदावा प्रस्तुत करते हैं तब इस पश्चातवर्ती बदलाव के आधार पर वादी को भी वाद में संशोधन करने हेतु अनुमत किया जाना चाहिए। **237** **334**

Order 7 Rule 6 and Order 47 Rule 1 – Review – Scope of.

आदेश 7 नियम 6 एवं आदेश 47 नियम 1 – पुनर्विलोकन का विस्तार। **183 (ii)** **251**

Order 7 Rule 11 – (i) Question of limitation and rejection of plaint.

(ii) Compromise decree – Can be challenged by person who was not party.

आदेश 7 नियम 11 – (i) परिसीमा का प्रश्न एवं वादपत्र का नामंजूर किया जाना।

(ii) समझौता डिक्री – ऐसे व्यक्ति के द्वारा चुनौती दी जा सकती है जो उसमें पक्षकार नहीं था। **124** **167**

Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – (i) Object of the provision explained.

(ii) Whether documents filed with plaint can be taken into consideration for deciding application under Order 7 Rule 11?

(iii) Test for exercising power under Order 7 Rule 11.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iv) Stage at which such powers may be exercised. (v) Whether plaint may be rejected being barred by limitation? Held, Yes. **आदेश 7 नियम 11** – वादपत्र नामंजूर किया जाना – (i) प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। (ii) क्या आदेश 7 नियम 11 के आवेदन का निराकरण करते समय वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है? (iii) आदेश 7 नियम 11 की शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी। (iv) प्रक्रम जिस पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। (v) क्या वादपत्र परिसीमा से बाधित होने के आधार पर नामंजूर किया जा सकता है? अभिनिर्धारित, हां।	**286 (i) - (v)**	**393**
Order 7 Rule 11 and Order 8 Rule 6A – (i) Whether a plaint can be rejected on the ground of limitation under Order 7 Rule 11 CPC? (ii) Counter-claim – What constitutes? Whether counter-claim can be treated as clarificatory or supplementary in nature to the written statement? **आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 8 नियम 6क** – (i) क्या सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के अधीन कोई वाद परिसीमा काल के आधार पर नामंजूर किया जा सकता है? (ii) प्रतिदावा – क्या होता है? क्या प्रतिदावा को लिखित कथन का स्पष्टीकरण या अनुपूरक माना जा सकता है?	**63**	**86**
Order 7 Rule 11 (d) – Rejection of plaint – Plaint cannot be rejected on issues of limitation and *res judicata*. **आदेश 7 नियम 11 (घ)** – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादपत्र परिसीमा एवं पूर्वन्याय के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है।	**184**	**253**
Order 7 Rule 14 and Order 18 Rule 4 – Admissibility of documents – When to be looked into? **आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 18 नियम 4** – दस्तावेजों की ग्राह्यता – कब विचार में ली जानी चाहिए?	**287**	**396**
Orders 7, 21 & 41 and Sections 5 & 11 – (i) Stage when court fees is payable. (ii) Determination of court fees – Issue of court fees is always liable to be decided as a preliminary issue. (iii) Application of Order 7 Rule 11 CPC in appeal. (iv) Execution of decree – If Appellate Court has not stayed the execution of decree, it is executable.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
आदेश 7, 21 और 41 एवं धाराएं 5 और 11 – (i) स्तर जब न्यायालय शुल्क देय होता है। (ii) न्यायालय शुल्क का निर्धारण – न्यायालय शुल्क का विवाद्यक प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में ही निर्धारित किया जाना चाहिए। (iii) अपील में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना। (iv) डिक्री का निष्पादन – यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन को स्थगित नहीं किया गया है तो वह निष्पादन योग्य है।	**13**	**15**
Order 8 Rule 1 – Written statement – Prescribed period of 90 days for filing – Nature of. **आदेश 8 नियम 1** – लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए 90 दिवस की अवधि विहित है – प्रकृति।	**238***	**335**
Order 8 Rule 6-A – Counter-claim can be filed after filing of written statement and not mandatory to file with the written statement. **आदेश 8 नियम 6–क** – प्रतिदावा लिखित कथन प्रस्तुत करने के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिदावा लिखित कथन के साथ प्रस्तुत करना आज्ञापक नहीं है।	**185**	**254**
Order 9 Rule 4 – See Section 5 of the Limitation Act, 1963. **आदेश 9 नियम 4** – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।	**125**	**168**
Order 11 Rule 21 (2) – Once suit has been dismissed under Order 11 Rule 21 of the Code sub-rule (1) by virtue of sub-rule (2), plaintiff is debarred to file fresh suit. **आदेश 11 नियम 21 (2)** – जब एक बार संहिता के आदेश 11 नियम 21 के अंतर्गत वाद खारिज हो चुका हो, तब उप–नियम (2) के आधार पर वादी नया वाद प्रस्तुत करने से वर्जित हो जाता है।	**239***	**335**
Order 14 Rule 2 – Preliminary issue – Question of law – When cannot be decided as preliminary issue? **आदेश 14 नियम 2** – प्रारंभिक विवाद्यक – विधि संबंधी प्रश्न – कब प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में निराकृत नहीं किए जा सकते हैं?	**288**	**397**
Order 14 Rule 5 – Issue as to maintainability of the suit in absence of consequential relief of possession when to be framed? **आदेश 14 नियम 5** – आधिपत्य के पारिणामिक अनुतोष के अभाव में वाद की प्रचलनशीलता संबंधी वादप्रश्न कब विरचित किया जाना चाहिए?	**126**	**169**
Order 16 Rules 1, 6 and 7 – Summoning of witnesses and documents. **आदेश 16 नियम 1, 6 एवं 7** – साक्षियों एवं दस्तावेजों का आहूत किया जाना।	**240***	**336**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 17 Rule 1 – Adjournment – Duties of the Members of Bar – Delineated.		
आदेश 17 नियम 1 – स्थगन – अभिभाषक संघ के सदस्यों के कर्तव्य – उद्धरित किए गए।	**6 (i)**	**5**
Order 20 Rule 12 (1) (c) (iii) – How much of mesne profit can be recovered from the date of decree.		
आदेश 20 नियम 12 (1) (ग) (iii) – आज्ञप्ति दिनांक से कितनी अवधि का अन्तःकालीन लाभ वसूल किया जा सकता है।	**7**	**7**
Order 20 Rule 18 and Order 22 Rule 5 – Partition suit – Amendment in preliminary decree.		
Res Judicata – Legal Representative – Under Order 22 Rule 5 of the Civil Procedure Code, limited question relating to the LR is decided only for the purpose of bringing the LRs on record which does not operate as *res judicata*.		
आदेश 20 नियम 18 एवं आदेश 22 नियम 5 – विभाजन का दावा – प्रारंभिक आज्ञप्ति में संशोधन।		
प्रांगन्याय – विधिक प्रतिनिधि – सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के उद्देश्य मात्र से विधिक प्रतिनिधि से संबंधित सीमित प्रश्न का निर्धारण किया जाता है, जो कि प्रांगन्याय का प्रभाव नहीं रखता है।	**8* (i) & (ii)**	**9**
Order 21 Rule 30 – Execution of money decree for maintenance.		
आदेश 21 नियम 30 – भरण–पोषण राशि की डिक्री का निष्पादन।	**203 (ii)**	**279**
Order 21 Rule 35 (3) – Delivery of possession – Use of police force by executive authority.		
आदेश 21 नियम 35 (3) – आधिपत्य का परिदान – निष्पादक प्राधिकारी द्वारा पुलिस बल का उपयोग।	**186**	**256**
Order 21 Rule 65 (as applicable in State of M.P.) – Auction sale – Auction proposal reserved for hearing objection – Does not amount to acceptance of bid.		
आदेश 21 नियम 65 (मध्यप्रदेश राज्य में यथा लागू) – नीलामी बिक्री – नीलामी प्रस्ताव आपत्ति पर सुनवाई हेतु नियत – बोली स्वीकार नहीं की गई।	**241***	**336**
Order 21 Rule 85 – Execution – Auction proceedings – Executing Court has no authority or jurisdiction to extend period to deposit balance amount of purchase money.		
आदेश 21 नियम 85 – निष्पादन – नीलामी कार्यवाहियां – निष्पादन न्यायालय को शेष क्रय राशि जमा करने के लिये समयावधि बढ़ाने का कोई क्षेत्राधिकार या शक्ति नहीं है।	**242***	**337**
Order 21 Rule 90 – See Section 5 of the Limitation Act, 1963.		
आदेश 21 नियम 90 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।	**318**	**440**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 22 Rules 1 to 5 – Substitution of legal representatives in matrimonial disputes. **आदेश 22 नियम 1 से 5** – वैवाहिक मामलों में विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन।	**64**	**88**
Order 22 Rule 3 – Legal representatives – Right to claim relief in suit. **आदेश 22 नियम 3** – विधिक प्रतिनिधि – वाद में अनुतोष का दावा करने का अधिकार।	**65**	**89**
Order 22 Rules 5 and 12 – Limitation to bring legal heirs on record which applies to suits, does not apply in execution proceedings. **आदेश 22 नियम 5 एवं 12** – विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने की परिसीमा, जो कि वादों के लिये लागू होती है, निष्पादन कार्यवाहियों में लागू नहीं होती है।	**127**	**170**
Order 23 Rule 3 and Order 43 Rule 1-A – (i) Compromise decree – Against a compromise decree an appeal is maintainable. (ii) Re-call of compromise decree – Whether an application can be filed for recall/ review of the compromise decree? **आदेश 23 नियम 3 एवं आदेश 43 नियम 1–क** – (i) समझौता डिक्री – समझौता डिक्री के विरूद्ध अपील संधारणीय है। (ii) समझौता डिक्री को वापस लेना – क्या समझौता डिक्री को वापस लेने या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?	**9**	**10**
Order 23 Rule 3A, Order 41 Rules 1A and 22 – (i) Challenge to compromise decree. (ii) In absence of a cross-appeal or cross-objection, modification of decree in appeal. (iii) Appeal – Challenge to adverse findings in decree by respondents. **आदेश 23 नियम 3क, आदेश 41 नियम 1क एवं 22** – (i) समझौता डिक्री को चुनौती दिया जाना। (ii) प्रति अपील अथवा प्रत्याक्षेप के अभाव में अपील में डिक्री का उपांतरण। (iii) अपील – प्रत्यर्थी द्वारा डिक्री में प्रतिकूल निष्कर्ष को चुनौती दिया जाना।	**10**	**13**
Order 32 Rule 5 – Effect of absence of formal order of appointment of next friend or *guardian ad litem* by the Court. **आदेश 32 नियम 5** – न्यायालय द्वारा वाद मित्र या वादकालीन संरक्षक की नियुक्ति के औपचारिक आदेश के अभाव का प्रभाव।	**128**	**171**
Order 33 Rule 1 – (i) Indigent person – Determination of indigency. (ii) Indigent person; appeal by. **आदेश 33 नियम 1** – (i) निर्धन व्यक्ति – निर्धनता का निर्धारण। (ii) निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील।	**66**	**90**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Order 39 Rules 1 and 2 – Temporary injunction – Encroachment – State has special provisions u/s 248 MPLRC for dispossessing the encroacher – Court cannot restrain the State from dispossessing the plaintiff unless and until *prima facie* it is shown that the plaintiffs are having any title in the property in dispute.

आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अस्थायी व्यादेश – अतिक्रमण – राज्य के पास मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमणकारी को बेकब्जा करने हेतु विशेष प्रावधान है – न्यायालय राज्य को वादी को बेकब्जा करने से अवरूद्ध नहीं कर सकता जब तक कि प्रथम दृष्टया यह न दिखाया गया हो कि वादी विवादित संपत्ति में कोई स्वामित्व रखता है। **243*** **337**

Order 39 Rule 2-A – An application under Order 39 Rule 2-A is maintainable only during pendency of civil suit.

आदेश 39 नियम 2–क – आदेश 39 नियम 2–क के अधीन आवेदन मात्र व्यवहार वाद के लंबित रहने के दौरान ही पोषणीय है। **129** **173**

Order 39 Rule 2-A – Breach of injunction and Willful disobedience, how to be proved?

आदेश 39 नियम 2–क – व्यादेश का भंग और जानबूझकर अवज्ञा, कैसे साबित किया जा सकता है? **11** **14**

Order 41 Rules 17, 19 and 21 – (i) Dismissal – Effect of absence of appellant on date of hearing.

(ii) Ex-parte decree – Passing *ex-parte* decree in absence of respondent after hearing appeal.

आदेश 41 नियम 17, 19 एवं 21 – (i) खारिजी – सुनवाई दिनांक पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति का प्रभाव।

(ii) एकपक्षीय डिक्री – सुनी गई अपील में प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में पारित एकपक्षीय डिक्री। **289** **398**

Order 41 Rule 22 – Defendant has no right to file cross-objection in an appeal filed by the co-defendant against the decree passed in favour of plaintiff.

आदेश 41 नियम 22 – एक प्रतिवादी को सहप्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में पारित डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में प्रत्याक्षेप दायर करने का अधिकार नहीं है। **130** **174**

Order 41 Rule 22 – Effect of dismissal of appeal on the cross-objection.

आदेश 41 नियम 22 – अपील खारिज किए जाने का प्रत्याक्षेप पर प्रभाव। **273** **376**

Order 41 Rules 23 and 23-A – Remand – When each and every oral and documentary evidence is appreciated by the Trial Court and every issue was decided on the basis of available evidence.

आदेश 41 नियम 23 एवं 23–क – प्रतिप्रेषण – जब विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन कर लिया गया हो और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक वादप्रश्न निर्णीत कर दिये गये हों। **131** **175**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 41 Rules 23, 23A, 27 and Order 9 Rule 13 – Remand in civil case – The first appellate court ought to have considered the appeal on merit and in case the appellate court finds it to be a fit case for reversal then only it can remand the case to the Trial Court.		
आदेश 41 नियम 23, 23क, 27 एवं आदेश 9 नियम 13 – व्यवहार वाद में प्रतिप्रेषण – प्रथम अपीलीय न्यायालय की गुण–दोष के आधार पर ही अपील को विचारित करना था एवं यदि अपीलीय न्यायालय निर्णय को अपास्त किया जाना उचित समझते केवल तब ही प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था।	**244**	**338**
Order 41 Rule 27 – Additional evidence – If proposed documents are not of such material documents which may change the fate of litigation conclusively, then application filed under Order 41 Rule 27 may be rejected.		
आदेश 41 नियम 27 – अतिरिक्त साक्ष्य – यदि प्रस्तावित दस्तावेज ऐसे तात्विक दस्तावेज नहीं हैं जो निर्णायक रूप से मुकदमेबाजी के परिणाम को बदल सकते हैं तब आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दायर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।	**245**	**339**
Order 41 Rule 27 – Production of additional evidence when permissible.		
आदेश 41 नियम 27 – अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कब अनुज्ञेय है।	**317 (iii)**	**437**
COMMERCIAL COURTS ACT, 2015		
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015		
Section 16 – See Order 8 Rule 1 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 16 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 1।	**238***	**335**
COMPANIES ACT, 2013		
कंपनी अधिनियम, 2013		
Section 430 – See Section 9 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 430 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9।	**290**	**400**
CONSTITUTION OF INDIA :		
भारत का संविधान :		
Article 20 (3) and 142 – See Sections 53, 53-A and 311-A of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 20 (3) एवं 142 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 53, 53–क एवं 311–क।	**14**	**18**
Article 21 – See Section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	**254**	**352**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Article 21 – Under-trial prisoners and medical treatment.		
अनुच्छेद 21 – विचाराधीन बंदी और चिकित्सीय उपचार।	**12***	**15**
Article 39-A – Legal aid – Appointment of *Amicus Curiae* by Court – Directions issued to ensure competent legal aid and fair trial.		
अनुच्छेद 39–क – विधिक सहायता – न्यायालय द्वारा न्याय मित्र की नियुक्ति – सक्षम विधिक सहायता और ऋजु विचारण सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।	**187 (i) & (iii)**	**257**
Article 136 – See Section 372 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 136 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372।	**79**	**105**
Article 141 – See Section 24 (2) of the The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.		
अनुच्छेद 141 – देखें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2)।	**227**	**322**
CONSUMER PROTECTION ACT, 1986		
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986		
– Medical negligence – A child reduced to a vegetative state after surgery because of medical negligence must be adequately compensated and factors to be taken into account while awarding compensation in such cases.		
– चिकित्सीय उपेक्षा – चिकित्सीय उपेक्षा के कारण शल्य क्रिया के पश्चात् शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो चुके बालक को पर्याप्त प्रतिकर दिया जाना चाहिए एवं ऐसे मामलों में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक।	**132**	**177**
Section 2 (1) (d) – Consumer – Definition – Beneficiary under the policy is definitely a consumer.		
धारा 2 (1) (घ) – उपभोक्ता – परिभाषा – पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थी निश्चित ही उपभोक्ता है।	**246 (i)**	**340**
CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971		
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971		
Sections 2 (c) and 12 – Maligning and scandalizing the Court during lunch hour into chamber amount to criminal contempt of Court.		
धाराएं 2 (ग) एवं 12 – भोजन अवकाश के दौरान विश्राम कक्ष में न्यायालय की निन्दा करना एवं उस पर दोषारोपण करना न्यायालय के आपराधिक अवमान की श्रेणी में आता है।	**133**	**177**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CONTRACT ACT, 1872		
संविदा अधिनियम, 1872		
Section 10 – See Section 34 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 10 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	**173**	**238**
Sections 32, 56 and 65 – Interpretation of contract: Rules of – *Force majeure* clause and doctrine of frustration – Effect of – Explained.		
धाराएं 32, 56 एवं 65 – संविदा के निर्वचन के नियम – *फोर्स मेज्योर* खण्ड एवं विफलीकरण का सिद्धांत – प्रभाव – समझाया गया।	**291**	**401**
Sections 70, 73 and 74 – Breach of contract – Remedies – Which provision of the Act is applicable when limits of liquidated damages are stipulated for?		
धाराएं 70, 73 एवं 74 – संविदा का भंग – उपचार – जहां नगद क्षति की सीमा निर्धारित की गई हो, वहां अधिनियम का कौन सा प्रावधान लागू होगा?	**67**	**92**
Sections 73 and 74 – Breach of contract; remedies for – Forfeiture of security deposit and detention of machinery, when available?		
धाराएं 73 एवं 74 – संविदा के उल्लंघन पर उपचार – सुरक्षा निधि का समपहरण एवं मशीनरी का परिरोध, कब उपलब्ध है?	**188***	**260**
Sections 148 and 151 – Insurance – Insurer is liable to pay value of damaged/destructed goods as shown in the receipts issued by the warehouse on the date of storage to farmers. Bailer and bailee – A person handing over his produce/goods to any warehouse on rent as a bailer and warehouse accepts this as a bailee and such relationship does not create a relationship based only on trust.		
धाराएं 148 एवं 151 – बीमा – बीमाकर्ता किसानों को क्षतिग्रस्त/नष्ट वस्तुओं के उसी मूल्य का भुगतान करने हेतु दायी है जो कि वेयरहाउस द्वारा भंडारण की तिथि को जारी की गई रसीदों में दर्शाया गया है। उपनिधाता एवं उपनिहिती – एक व्यक्ति अपने उत्पाद/वस्तुओं को किसी वेयरहाउस को किराये पर उपनिधाता के रूप में सौंपता है एवं वेयरहाउस उसे एक उपनिहिती के रूप में स्वीकार करता है और ऐसा संबंध मात्र विश्वास पर आधारित संबंध का सृजन नहीं करता है।	**246 (ii) & (iii)**	**340**
COURT FEES ACT, 1870		
न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870		
Sections 12 and 35 – See Orders 7, 21 & 41 and Sections 5 & 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 12 एवं 35 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7, 21 एवं 41 और धाराएं 5 एवं 11।	**13**	**15**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CRIMINAL PRACTICE:		
आपराधिक प्रथाः		
– See Section 372 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372।	**79**	**105**
– Parameter to be considered while imposition of sentence.		
– सजा अधिरोपित किए जाते समय विचार में लिए जाने वाले कारक।	**292***	**402**
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973		
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		
Sections 2(h), 156 (3) and 173 (8) – (i) Words 'Investigation', 'enquiry' and 'trial', meaning of. (ii) Further investigation empowerment of Police. (iii) Power of Magistrate to order further investigation after receipt of report u/s 173(2) extends till commencement of the trial.		
धाराएं 2(ज), 156 (3) एवं 173 (8) – (i) शब्द 'अन्वेषण', 'जांच' और 'विचारण' का तात्पर्य। (ii) पुलिस की आगे अन्वेषण की शक्तियां। (iii) मजिस्ट्रेट की आगे अन्वेषण आदेशित करने की शक्ति धारा 173 (2) के अन्तर्गत प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् विचारण प्रारंभ होने तक विस्तारित होती है।	**134**	**179**
Sections 31, 173, 218, 219 and 220 – Final report; amalgamation of – Whether more than one FIR may be amalgamated into a single final report ?		
धाराएं 31, 173, 218, 219 एवं 220 – अंतिम प्रतिवेदनों का संयोजन – क्या एक से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक अंतिम प्रतिवेदन में संयोजित किया जा सकता है?	**46 (ii)**	**59**
Sections 53, 53-A and 311-A [inserted by (Amendment) Act 25 of 2005] – Voice sample of accused for investigation – Recording of – Permissibility.		
धाराएं 53, 53–क एवं 311–क [2005 के 25 (संशोधन) अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित] – अन्वेषण के लिये अभियुक्त की आवाज के नमूने के अभिलेखन की अनुज्ञेयता।	**14**	**18**
Sections 53 and 54-A – DNA test – When can be ordered?		
धाराएं 53 एवं 54–ए – डी.एन.ए. परीक्षण – कब आदेशित किया जा सकता है?	**15**	**19**
Section 91 – Summoning of electronic evidence at the stage of investigation.		
धारा 91 – अन्वेषण के प्रक्रम पर इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का समन किया जाना।	**189**	**260**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 125 – Maintenance – Second marriage contracted during the pendency of an appeal from a decree of divorce is not ab initio void and certainly not when such an appeal is filed after expiry of the period of limitation – Wife entitled for maintenance.		
धारा 125 – भरण–पोषण – विवाह विच्छेद के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के लंबित रहने के दौरान द्वितीय विवाह प्रारंभतः शून्य नहीं है और निश्चित रूप से जबकि ऐसी अपील परिसीमा अवधि का अवसान होने के उपरांत प्रस्तुत की गई हो – पत्नी भरण–पोषण की हकदार है।	**260 (ii)**	**362**
Section 125 – Maintenance – Whether a wife, who has been divorced by the husband, on the ground that the wife has deserted him, is entitled to claim maintenance?		
धारा 125 – भरण–पोषण – क्या एक पत्नी, जिसे पति का परित्याग किए जाने के कारण तलाक प्रदान किया गया है, भरण–पोषण प्राप्त करने की पात्र है?	**16**	**20**
Section 125 – See Sections 45, 112 and 114 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 125 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 45, 112 एवं 114।	**308**	**427**
Sections 125 (1), 125 (5), 127 (2) and 362 – In the case of non-compliance of the settlement by the husband in a maintenance case, wife's claim of maintenance can be revived by the Court.		
धारा 125 (1), 125 (5), 127 (2) एवं 362 – भरण–पोषण के मामले में पति द्वारा व्यवस्थापन का अनुपालन न करने की दशा में पत्नी के भरण–पोषण के दावे का न्यायालय द्वारा पुनः प्रवर्तन किया जा सकता है।	**135**	**182**
Section 125 (3) – Whether imprisonment for a period exceeding one month can be imposed for default of payment of arrears of maintenance for more than a month?		
धारा 125 (3) – क्या एक माह से अधिक भरण–पोषण के बकाया के लिए एक माह से अधिक कारावास अधिरोपित किया जा सकता है?	**17**	**24**
Section 145 – (i) Maintainability of Revision against *quasi–final* or intermediate order. (ii) Proceeding u/s 145 Cr.P.C. be stayed only when *factum* of possession is sub-judice in the civil suit.		
धारा 145 – (i) अर्द्ध–अंतिम अथवा मध्यवर्ती आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की प्रचलनशीलता। (ii) द.प्र.सं. की धारा 145 के अधीन कार्यवाही मात्र तब स्थगित की जा सकती है, जब सिविल वाद में आधिपत्य का तथ्य न्यायाधीन हो।	**68**	**93**
Section 154 – FIR – Delay in lodging – Effect of.		
धारा 154 – प्रथम सूचना रिपोर्ट – लेख कराने में विलंब – प्रभाव।	**136 (ii)**	**182**
Section 154 – FIR and inquest report – Mention of inquest number in FIR; effect of.		
धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन – प्रथम सूचना प्रतिवेदन में मृत्यु समीक्षा नंबर का उल्लेख; प्रभाव।	**94 (iii)**	**131**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 154 and 173 (8) – Registration of second FIR of the same incident – When permissible?

धाराएं 154 एवं 173 (8) – एक ही घटना के संबंध में द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन – कब अनुज्ञेय है? **18 (i) 25**

Sections 154 and 197 – See Sections 13(2) r/w/s 13(1)(e), 17 and 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धाराएं 154 एवं 197 –देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ङ), 17 एवं 19। **223 317**

Sections 156 (3), 173, 190 and 200 – (i) Second complaint; maintainability of.

(ii) Second protest petition; maintainability of.

धाराएं 156 (3), 173, 190 एवं 200 – (i) द्वितीय परिवाद; पोषणीयता।

(ii) द्वितीय परिवाद याचिका; पोषणीयता। **293 403**

Section 157 – Delay in sending copy of FIR to Magistrate – Effect of.

धारा 157 – मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेजने में विलंब का प्रभाव। **294* 407**

Section 161 – Recording of statement of witnesses by police; delay in – Effect.

धारा 161 – पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन लेख करने में विलंब – प्रभाव। **137 (ii) 185**

Sections 161 and 164 – Statement of witness – Delay in recording – Effect.

धाराएं 161 एवं 164 – साक्षियों के कथन – अभिलिखित किये जाने में विलम्ब – प्रभाव। **37 (ii) 47**

Sections 166-A and 357-A – See Sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB and 376E of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 166–क एवं 357–क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख एवं 376ङ। **213 294**

Sections 167, 309, 437 and 439 – (i) Bail – Addition of new and grave offences against an accused enlarged on bail – Whether a ground to re-arrest such accused?

(ii) Remand – Sections 167 and 309 CrPC, applicability of.

धाराएं 167, 309, 437 एवं 439 – (i) जमानत – जमानत पर रिहा अभियुक्त के विरूद्ध नए तथा गंभीर अपराध जोड़ा जाना – क्या यह अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार करने का आधार है?

(ii) रिमाण्ड – धाराएं 167 एवं 309 द.प्र.सं. की प्रयोज्यता। **19 28**

Section 173 – First information reports related to common allegations may be clubbed and accused may be proceeded at one place.

धारा 173 – समान अभिकथनों से संबंधित कई प्रथम सूचना रिपोर्ट संयुक्त की जा सकती हैं एवं अभियुक्त पर एक ही स्थान पर कार्यवाही की जा सकती है। **138 190**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 173 (2) and 190 – Which Closure Report can be adopted by Magistrate?		
धाराएं 173 (2) एवं 190 – कौन सी खात्मा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की जा सकती है?	**69**	**94**
Section 174 – Purpose of Inquest Report u/s 174.		
धारा 174 – धारा 174 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का उद्देश्य।	**190 (i)**	**261**
Section 173 (8) – Further investigation – Co-accused against whom the charge-sheet is already filed and no relief of further investigation is sought has no right of hearing.		
धारा 173 (8) – अतिरिक्त अन्वेषण – सह–अभियुक्त जिसके विरुद्ध पूर्व में ही अभियोगपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो और उसके विरुद्ध पश्चात्वर्ती अन्वेषण का अनुतोष प्रार्थित न किया गया हो उसे सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।	**295**	**407**
Sections 190 and 202 – Protest petition, how to be dealt with?		
धाराएं 190 एवं 202 – प्रतिवाद याचिका, पर किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए?	**20**	**30**
Sections 193 and 209 – Cognizance by Special Court – Committal of accused.		
धाराएं 193 एवं 209 – विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान – अभियुक्त का उपार्पण।	**30**	**39**
Section 197 – Employees of Public Sector Corporations are not entitled to protection u/s 197 as 'public servant'.		
धारा 197 – सरकारी क्षेत्र निगमों के कर्मचारी धारा 197 के अन्तर्गत ''लोक सेवक'' के रूप में संरक्षण के हकदार नहीं है।	**21***	**32**
Section 197 – Sanction for prosecution – (i) Object explained. (ii) Sanction when necessary? (iii) Stage at which necessity of sanction may be examined.		
धारा 197 – अभियोजन के लिए स्वीकृति – (i) उद्देश्य समझाया गया। (ii) स्वीकृति कब आवश्यक है? (iii) प्रक्रम जब स्वीकृति की आवश्यकता का परीक्षण किया जा सकता है।	**296**	**408**
Section 197 – Whether protection available to a public servant while in service, should also be available after his retirement? No.		
धारा 197 – क्या लोक सेवक को सेवा के दौरान उपलब्ध संरक्षण उसकी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उपलब्ध होना चाहिए? नहीं।	**191**	**262**
Section 205 – Personal attendance of accused – Consideration and conditions.		
धारा 205 – अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति – विचारणीय तथ्य एवं शर्तें।	**192**	**265**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 207 – See Sections 3 and 65-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 207 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 65–बी।	**215**	**300**
Section 216 – (i) Whether charges can be added or altered even after the completion of evidence, arguments and reserving of the judgment? Held, Yes. (ii) Whether evidentiary value of material already brought on record is to be taken into consideration? Held, No.		
धारा 216 – (i) क्या साक्ष्य एवं तर्क पूर्ण होने और निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाने के बाद भी आरोप परिवर्द्धित या परिवर्तित किए जा सकते हैं? अभिनिर्धारित, हां। (ii) आरोप में परिवर्द्धन या परिवर्तन – क्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का साक्ष्यिक मूल्य विचार में लिया जाना चाहिए? अभिनिर्धारित, नहीं।	**247**	**342**
Sections 225 and 301 – Sessions trial – Whether counsel engaged by *victim/de-facto* complainant may be permitted to cross-examine defence witness after cross-examination by public prosecutor?		
धाराएं 225 एवं 301 – सत्र विचारण – क्या पीड़ित या वास्तविक परिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को लोक अभियोजक के द्वारा बचाव साक्षी का प्रतिपरीक्षण कर लिये जाने के पश्चात् उसी साक्षी से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है?	**70**	**95**
Section 227 – Discharge; application for – Consideration of.		
धारा 227 – उन्मोचन के लिए आवेदन – विचार।	**71***	**96**
Section 227 – Discharge of accused – Parameters.		
धारा 227 – अभियुक्त का उन्मोचन – मापदण्ड।	**139**	**191**
Sections 227 and 228 – See Sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 227 एवं 228 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।	**248**	**343**
Sections 227 and 309 – Expeditious disposal of cases *vis-a-vis* fairness and opportunity to the accused.		
धाराएं 227 एवं 309 – प्रकरणों का शीघ्र निराकरण एवं निष्पक्षता और अभियुक्त को अवसर।	**187 (ii)**	**257**
Sections 227 and 397 – Order of discharge while exercising revisional jurisdiction – At this stage, final test of guilt is not to be applied.		
धाराएं 227 एवं 397 – पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उन्मोचन का आदेश – इस स्तर पर दोषसिद्धि के अंतिम परीक्षण की जांच नहीं की जाती है।	**140**	**193**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 228 – Framing of charges – Offences of cheating and criminal breach of trust by public servant.		
धारा 228 – आरोपों की विरचना – लोक सेवक द्वारा न्यास का आपराधिक भंग एवं छल के अपराध।	**72***	**96**
Sections 235(2) and 354 – (i) Non-examination of the officer of the mobile company when cannot be said to be fatal to the case of the prosecution. (ii) Hostile witness – Extent to which prosecution can rely upon. (iii) Hearing on question of sentence. (iv) Mitigating circumstances.		
धाराएं 235(2) एवं 354 – (i) मोबाइल कंपनी के अधिकारी का परीक्षण न कराया जाना कब अभियोजन के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है। (ii) पक्षद्रोही साक्षी – स्तर जहां तक अभियोजन उस पर विश्वास कर सकता हो। (iii) दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना। (iv) लघुतरकारी परिस्थितियाँ।	**313**	**432**
Section 239 – Issue urged by the accused can be decided properly during trial after evidence is adduced by the parties.		
धारा 239 – अभियुक्त द्वारा उठाये गये आधारों का निराकरण पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत उचित रूप से किया जा सकता है।	**152**	**211**
Sections 273, 299 and 317 – Recording of evidence in absence of accused – Validity of.		
धाराएं 273, 299 एवं 317 – अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना – वैधता।	**141***	**194**
Sections 273 and 317 – Criminal trial – Recording of the statements of the witnesses in absence of the accused.		
धाराएं 273 एवं 317 – आपराधिक विचारण – अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी के कथन अभिलिखित किया जाना।	**314**	**434**
Section 300 – Double jeopardy – Applicability of – Whether mentioning of different penal provisions in later FIR can be considered as different ingredients justifying it? Held, No.		
धारा 300 – दोहरे दण्ड का सिद्धांत – प्रयोज्यता – क्या पश्चात्वर्ती प्रथम सूचना रिपोर्ट में भिन्न प्रावधानों का उल्लेख उसे उचित ठहराने वाले भिन्न संघटक माने जा सकते हैं? अभिनिर्धारित, नहीं।	**249***	**344**
Section 302 – Permission to conduct prosecution.		
धारा 302 – अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा।	**22**	**32**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 309 (2)(c) – Cross-examination of witness – Right closed by Trial Court.		
धारा 309 (2)(ग) – साक्षी का प्रतिपरीक्षण – विचारण न्यायालय द्वारा अधिकार समाप्त कर दिया जाना।	**73***	**97**
Section 311 – Recalling of witnesses on the ground of incompetency of previous lawyer.		
धारा 311 – पूर्व अधिवक्ता की अक्षमता के आधार पर साक्षियों को पुनः बुलाया जाना।	**74***	**98**
Section 313 – Examination of accused – Accused's attention should be drawn to every inculpatory material so as to enable him to explain it.		
धारा 313 – अभियुक्त परीक्षण – अभियुक्त का ध्यान ऐसे प्रत्येक अभियोगात्मक तत्वों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें उसे स्पष्ट करने का अवसर उपलब्ध हो सके।	**75**	**98**
Section 313 – Examination of accused – Admission made during – Use of.		
धारा 313 – अभियुक्त परीक्षण – इस दौरान की गई स्वीकृति का उपयोग।	**76 (ii)**	**100**
Section 313 – Examination of accused – Inculpatory admissions – Whether to be relied upon? Held, Yes.		
धारा 313 – अभियुक्त का परीक्षण – अभियोगात्मक स्वीकृतियाँ – क्या विश्वास करने योग्य है? अभिनिर्धारित, हाँ।	**250 (i)**	**345**
Section 313 – See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 313 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**206**	**282**
Section 313 – See Sections 138, 118(a) and 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धारा 313 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138, 118(क) एवं 139।	**221**	**311**
Section 319 – Order of summoning – Exercise of power u/s 319 – Test to be applied.		
धारा 319 – समन करने का आदेश – धारा 319 की शक्ति का उपयोग – परीक्षण की कसौटी।	**78***	**105**
Section 319 – Summoning of accused – Degree of proof required.		
धारा 319 – अभियुक्त को समन किया जाना – आवश्यक प्रमाण की मात्रा।	**142**	**195**
Section 319 – Summoning of additional accused.		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को आहूत करना।	**77***	**104**
Section 319 – Summoning of additional accused – Standard of proof required for.		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को आहूत किया जाना – प्रमाण का अपेक्षित स्तर।	**23**	**33**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 319 – Summoning of accused – Exercise of discretion.		
धारा 319 – अभियुक्त को समन किया जाना – विवेकाधिकार का प्रयोग।	**193**	**266**
Section 354 – Death sentence; award of – Cases based on circumstantial evidence – Whether death sentence can never be awarded in cases based on circumstantial evidence?		
– Death sentence – Doctrine of "residual doubt" – Explained.		
धारा 354 – मृत्युदण्ड अधिरोपित किया जाना – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले – क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में मृत्युदण्ड कभी नहीं दिया जा सकता है?		
– मुत्युदण्ड – ''अवशिष्ट संदेह'' का सिद्धांत – व्याख्या की गई।	**89**	**121**
Section 360 – (i) Benefit of probation – Provisions of Section 360 CrPC, nature of.		
(ii) Benefit of probation – Distinction between the provisions of Section 360 CrPC and Sections 3 and 4 of the Probation of Offenders Act, 1958.		
धारा 360 – (i) परिवीक्षा का लाभ – धारा 360 द.प्र.सं. के प्रावधान की प्रकृति।		
(ii) परिवीक्षा का लाभ – द.प्र.सं. की धारा 360 एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धाराएं 3 एवं 4 के प्रावधानों के मध्य भेद।	**24**	**34**
Section 372 – (i) Appeal against conviction – Whether appellate court while hearing an appeal against conviction, convict accused for offences under which they were acquitted by the trial Court?		
(ii) Illegal order – Challenged by only one of several accused – Whether non-appealing accused can be benefited by setting aside such illegal order?		
धारा 372 – (i) दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील – क्या दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील पर सुनवाई करते हुए अपीलीय न्यायालय, उन अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकती है जिनमें वे विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए थे?		
(ii) अवैध आदेश – कई अभियुक्तगण में से केवल एक द्वारा चुनौती दी गई – क्या ऐसे अवैध आदेश को अपास्त करते हुए अपील न करने वाले अभियुक्तगण को भी लाभान्वित किया जा सकता है?	**79**	**105**
Section 377 – Appeal filed by the State against inadequate sentence – Accused may plead for either acquittal or reduction of sentence although no formal appeal against judgment was preferred by him.		
धारा 377 – राज्य द्वारा अपर्याप्त दण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति अथवा उसके विरूद्ध अभिलिखित दण्डादेश में कमी की याचना कर सकता है, यद्यपि उसने निर्णय के विरूद्ध औपचारिक अपील प्रस्तुत नहीं की है।	**297***	**410**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 386 – Remand – In a criminal case, remand is not to be ordered as a matter of course but in very rare circumstances.

धारा 386 – प्रतिप्रेषण – एक आपराधिक प्रकरण में, प्रतिप्रेषण का आदेश सामान्य अनुक्रम में जारी नहीं किया जाना चाहिए किंतु अत्यन्त असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। **251*** **350**

Section 386 – When order of acquittal recorded by trial court could be interfered.

धारा 386 – कब विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। **298*** **411**

Sections 389 and 436-A – Section 436-A has no application during the pendency of the appeal.

धाराएं 389 एवं 436–क – धारा 436–क की अपील के लंबन के दौरान कोई प्रयोज्यता नहीं है। **299** **411**

Section 394 – Appeal; abatement of – Whether entire appeal would be abated on the death of accused appellant, where appeal was preferred against sentence as well as fine? Held, No.

धारा 394 – अपील का उपशमन – क्या जहां कारावास के साथ–साथ अर्थदण्ड के विरुद्ध भी अपील की गई हो, वहां अभियुक्त अपीलार्थी की मृत्यु पर पूरी अपील उपशमित हो जाएगी? अभिनिर्धारित, नहीं। **252*** **351**

Sections 397 and 401 – Revision against order of dismissal of complaint – Grant of opportunity of hearing to accused.

धाराएं 397 एवं 401 – परिवाद खारिज करने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण – अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना। **300*** **412**

Section 427 (2) – Scope of Section 427 – Conviction of accused in three cases for offence u/s 138.

धारा 427 (2) – धारा 427 का विस्तार – तीन मामलों में अभियुक्त को धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया। **25*** **36**

Sections 437, 438 and 439 – Bail – Condition of cash deposit – Refund of such amount; entitlement of.

धाराएं 437, 438 एवं 439 – जमानत – नगद जमा करने की शर्त – ऐसी राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार। **194*** **267**

Sections 437, 438 and 439 – Bail – Conditions that may be imposed – Whether a condition of cash deposit in PM CARES fund or such similar fund while allowing bail application can be imposed by Courts?

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

धाराएं 437, 438 एवं 439 – जमानत – अधिरोपित की जाने योग्य शर्तें – क्या न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए पीएम केयर्स फंड अथवा ऐसे समान फंड में नगद राशि जमा करने की शर्त अधिरोपित की जा सकती हैं? **143** **196**

Sections 437 and 439 – (i) Bail – Factors to be considered while granting or cancelling bail – Explained.

(ii) Bail; cancellation of – Held, cancellation of bail is a harsh order and it must not be lightly resorted to.

धाराएं 437 एवं 439 – (i) जमानत – जमानत देने या निरस्त करते समय विचार किए जाने वाले कारक – व्याख्या की गई।

(ii) जमानत निरस्त किया जाना – अभिनिर्धारित, जमानत निरस्त किया जाना एक कठोर आदेश है और इसे बिना सोच–विचार किए अवधारित नहीं किया जाना चाहिए। **253** **351**

Sections 437 and 439 – See Sections 8, 10 and 12 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

धाराएं 437 एवं 439 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 8, 10 एवं 12। **80*** **107**

Section 438 – (i) Anticipatory bail – Reference made to larger Bench in the light of previous contradictory judgments, answered.

(ii) Whether anticipatory bail can be ordered to remain in force for a limited period so as to enable that person to seek regular bail from trial court?

(iii) Whether life of an anticipatory bail should end at the time and stage when the accused is summoned by the Court? Held, No.

धारा 438 – (i) अग्रिम जमानत – पूर्ववर्ती विरोधाभासी निर्णयों के आलोक में वृहद पीठ को प्रेषित संदर्भ, निर्णीत किया गया।

(ii) क्या अग्रिम जमानत को सीमित अवधि के लिए प्रभावी रहने का आदेश दिया जा सकता है ताकि ऐसा व्यक्ति विचारण न्यायालय से नियमित जमानत प्राप्त कर सके?

(iii) क्या अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने के समय और प्रक्रम पर अग्रिम जमानत का प्रभाव समाप्त हो जाना चाहिए? अभिनिर्धारित, नहीं। **254** **352**

Section 438 – Anticipatory bail – Where complaint does not make out a *prima facie* case for applicability of the provisions of the Scheduled Castes And Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

धारा 438 – अग्रिम जमानत – जब शिकायत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की प्रयोज्यता हेतु प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाती है। **144** **197**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 439 – Bail – Relevant factors.		
धारा 439 – जमानत – सुसंगत कारक।	**26**	**36**
Section 439 – Grant of interim bail – Economic offences having deep-rooted conspiracy and involving huge loss of investors' money.		
धारा 439 – अंतरिम जमानत प्रदान करना – आर्थिक अपराध जो षड़यंत्र की गहरी जड़े एवं निवेशकों के धन के व्यापक नुकसान को समाहित करते है।	**195**	**268**
Section 439 – See Section 37 of the N.D.P.S. ACT, 1985.		
धारा 439 – देखें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37।	**255**	**357**
Section 439 (2) – (i) Bail – Grant of – Power to grant bail u/s 439 of the Code is of wide amplitude – Factors to be considered. (ii) Bail, determining factors. (iii) Administration of justice – Grant or refusal of bail – Duty of Judge.		
धारा 439 (2) – (i) जमानत – प्रदान किया जाना – धारा 439 के अंतर्गत जमानत प्रदान किये जाने के विस्तृत आयाम हैं – विचार योग्य कारक। (ii) जमानत निर्धारण के कारक। (iii) न्यायिक प्रशासन – जमानत स्वीकार या अस्वीकार किया जाना – न्यायाधीश का कर्तव्य।	**196**	**269**
Section 451 – Interim custody of vehicle and Forest Act, 1927.		
धारा 451 – वन अधिनियम, 1927 एवं वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी।	**145**	**197**
CRIMINAL TRIAL:		
आपराधिक विचारण :		
– Appreciation of evidence of eye witness.		
– चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन।	**27**	**37**
– Appreciation of evidence and sentence of capital punishment.		
– साक्ष्य का मूल्यांकन एवं मृत्यु का दण्डादेश।	**81**	**108**
– Blood stains – Proof of Forensic examination – Benefit of doubt.		
– खून के धब्बे – फोरेंसिक परीक्षण का प्रमाण – संदेह का लाभ।	**82**	**109**
– Circumstantial evidence – The circumstances relied upon by the prosecution to prove the guilt of the accused has to be completed and lead to the conclusion that in all human probability the offence must have been committed by the accused.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– परिस्थितिजन्य साक्ष्य– अभियुक्त की दोषिता को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियां संपूर्ण होनी चाहिए और इस निष्कर्ष की ओर अग्रेषित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में अपराध मात्र अभियुक्त द्वारा ही किया गया हो।	256*	358
– Criminal Trial – Standard of proof.		
– आपराधिक विचारण में सबूत का स्तर।	190 (ii)	261
– Duty of prosecution.		
– अभियोजन का कर्तव्य।	28 (ii)	38
– Inquest and post-mortem report – Prevalency.		
– मृत्यु समीक्षा एवं शव–परीक्षण रिपोर्ट – अधिमानता।	198	275
– On the basis of observations, complaint u/s 166, 167, 201 to 204 IPC was filed – Effect of pending criminal trial.		
– टिप्पणियों के आधार पर भा.द.सं की धारा 166, 167, 201 से 204 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया – आपराधिक विचारण लंबित रहने का प्रभाव।	197	274
– See Sections 154 and 173(8) of the Criminal Procedure Code, 1973 and Section 45 of the Evidence Act, 1872		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 173(8) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45।	18	25
– See Sections 201, 302 r/w/s 34 and 364-A of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302 सहपठित धारा 34 एवं 364–क।	153	212
– See Sections 498-A and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 498–क एवं 302।	47	61
– (i) Sentence – Reduction – For reduction of sentence, detailed analysis of facts of the case, nature of injuries caused, weapons used, number of victims etc., have to be taken into consideration. (ii) Tests of sentencing for crimes – Crime test, criminal test and comparative proportionality test – Explained.		
– (i) दण्डादेश – लघुकरण – दण्डादेश के लघुकरण के लिए प्रकरण के तथ्य, कारित उपहतियों की प्रकृति, प्रयुक्त आयुध, आहत की संख्या आदि के विस्तृत विश्लेषण को विचार में लिया जाना चाहिए। (ii) अपराधों के लिये दण्डादेश की कसौटी – अपराध परीक्षण, अपराधी परीक्षण तथा तुलनात्मक समानुपातिक परीक्षण – समझाया गया।	199	275

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
EASEMENTS ACT, 1882		
सुखाचार अधिनियम, 1882		
Sections 12, 13 and 41 – Extinction on termination of necessity.		
धाराएं 12, 13 एवं 41 – आवश्यकता के पर्यवसान पर निर्वापण।	**29***	**38**
ELECTRICITY ACT, 2003		
विद्युत अधिनियम, 2003		
Section 151 and Second Proviso – See Sections 193 and 209 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 151 एवं द्वितीय परन्तुक – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 193 एवं 209।	**30**	**39**
EVIDENCE ACT, 1872		
साक्ष्य अधिनियम, 1872		
Section 3 – Convictions can be based solely on the evidence of the prosecutrix.		
धारा 3 – अभियोक्त्री की एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है।	**156**	**216**
Section 3 – Rape – Appreciation of evidence.		
धारा 3 – बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन।	**214***	**299**
Section 3 – See Sections 34, 300 Exception 4, 302 and 304 Part I of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग–एक।	**86***	**116**
Section 3 – See Sections 120B, 409 and 477A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 409 एवं 477क।	**91***	**127**
Section 3 – See Section 376(2)(1) (Prior to Amendment 2013) of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(1) (संशोधन 2013 के पूर्व)।	**99***	**141**
Section 3 – See Section 57 of the N.D.P.S. Act, 1985.		
धारा 3 – देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 57।	**324**	**448**
Sections 3 and 32 – Dying declaration – Principles reiterated.		
धाराएं 3 एवं 32 – मृत्युकालीन कथन – सिद्धान्त दोहराए गए।	**146**	**199**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 3 and 32 – Multiple dying declarations; appreciation of – Presence of family members while making dying declaration.		
धाराएं 3 एवं 32 – एकाधिक मृत्युकालिक कथन की विवेचना – मृत्युकालीन कथन देते समय परिवार के सदस्यों की उपस्थिति।	**83**	**111**
Sections 3 and 45 – Report of hand writing experts.		
धाराएं 3 एवं 45 – हस्तलेख विशेषज्ञों का प्रतिवेदन।	**92***	**128**
Sections 3 and 45 – (i) Contradiction and inconsistencies in evidence of eye-witnesses; effect of. (ii) Eye-witness; credibility of. (iii) Medical vs. ocular evidence – Inconsistencies; effect of. (iv) Expert evidence – Indecisive opininon – FSL report; effect of.		
धाराएं 3 एवं 45 – (i) चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में विरोधाभास और विसंगतियाँ – प्रभाव। (ii) चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता। (iii) चिकित्सीय विरूद्ध मौखिक साक्ष्य – विसंगतियाँ – प्रभाव। (iv) विशेषज्ञ साक्ष्य – एफ.एस.एल. रिपोर्ट में अनिर्णायक राय का प्रभाव।	**94**	**131**
Sections 3 and 65-B – (i) Memory card/pen-drive – Nature of evidence. (ii) Supply of electronic documents to accused u/s 207 of CrPC.		
धाराएं 3 एवं 65–ख – (i) मेमोरी कार्ड/पेन–ड्राईव – साक्ष्य की प्रकृति। (ii) दं.प्र.सं. की धारा 207 के अंतर्गत अभियुक्त को इलेक्ट्रानिक दस्तावेज प्रदाय किया जाना?	**215**	**300**
Sections 3, 65-B and 106 – Circumstantial evidence – Last seen theory – Does not by itself lead to an inference about guilt of accused. Electronic evidence, admissibility of – Whether objections as to admissibility of electronic evidence for want of certificate u/s 65 of the Evidence Act – Once waived at the time of recording of evidence can be raised during appeal.		
धाराएं 3, 65–ख एवं 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – स्वयमेव अभियुक्त की दोषिता के संबंध में अनुमान को इंगित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ग्राह्यता – क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता की आपत्ति, एक बार साक्ष्य अभिलेखन के स्तर पर परित्यक्त कर दिए जाने के उपरांत अपील के स्तर पर उठाई जा सकती है?	**76 (iii) & (iv)**	**100**
Sections 3 and 106 – See Section 364-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 106 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 364–क।	**98**	**138**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 3 and 113B – Presumption – facts which must be established before presumption is raised.		
धाराएं 3 एवं 113ख – उपधारणा – उपधारणा करने के पूर्व जो तथ्य साबित किए जाने चाहिए।	**87 (ii)**	**117**
Sections 6 and 24 to 27 – Extra-judicial confessions, appreciation of.		
धाराएं 6 एवं 24 से 27 – न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का मूल्यांकन।	**147 (iii)**	**202**
Section 8 – Motive is not an exact requirement under the Penal Code.		
धारा 8 – दण्ड संहिता के अधीन हेतुक निश्चित आवश्यकता नहीं है।	**148 (i)**	**207**
Sections 8, 11, 15 and 45 – See Sections 302 and 376 (2) (i) (As inserted by Amendment Act of 2013) of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 8, 11, 15 एवं 45 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 376 (2) (i) (2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अन्तः स्थापित)।	**210**	**287**
Section 9 – (i) Identification parade – Effect – If the eye-witness has not deposed about the identification.		
(ii) Recovery – The recovery will not stand vitiated merely because the place of recovery of dead body of victim was an open place.		
(iii) Veracity of DNA report – Effect of non-mentioning of time and duration of test.		
(iv) Examination of accused – Where conviction is recorded on the basis of circumstantial evidence, the statement of accused u/s 313 Cr.P.C. was relevant material.		
(v) Sentence – The pendency of large number of criminal cases against the accused persons might be a factor which could be taken note of for awarding a sentence but in any case, not a relevant factor for awarding capital punishment.		
धारा 9 – (i) शिनाख्तगी परेड – प्रभाव – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने पहचान के संबंध में कथन न किया हो।		
(ii) बरामदगी – केवल इसलिए बरामदगी दूषित नहीं होगी कि मृतक के शव की बरामदगी खुले स्थान से हुई है।		
(iii) डी.एन.ए. रिपोर्ट की शुचिता – केवल इसलिए कि डी.एन.ए. प्रतिवेदन में समय और परीक्षण की अवधि का उल्लेख नहीं है ऐसा प्रतिवेदन दूषित नहीं होगा।		
(iv) अभियुक्त परीक्षण – जहां दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अभिनिर्धारित की जाती है धारा 313 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त का कथन सुसंगत होगा।		
(v) दण्डादेश – अभियुक्त के विरुद्ध बड़ी संख्या में आपराधिक प्रकरणों का लंबित होना एक कारक हो सकता है जिसे दण्डादेश अधिरोपित करने में विचार में लिया जाये, परंतु किसी भी स्थिति में मृत्युदण्ड अधिरोपित करने में यह सुसंगत कारक नहीं होगा।	**263**	**366**
Section 9 – Test identification parade – Effect of non-holding.		
धारा 9 – शिनाख्त परेड नहीं कराए जाने का प्रभाव।	**200**	**276**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 9 – Test Identification Parade – Refusal to participate – Effect of.		
धारा 9 – पहचान परेड – भाग लेने से इंकार करने का प्रभाव।	**312 (i)**	**430**
Sections 9 and 45 – Cause of death – Determination of – Opinion of medical expert.		
धाराएं 9 एवं 45 – मृत्यु का कारण – निर्धारण – चिकित्सीय विशेषज्ञ का अभिमत।	**136 (i)**	**182**
Sections 11, 32, 114 and 154 – Hostile witness – Evidentiary value of.		
- Dying declaration – Oral – Credibility of.		
- Plea of alibi – Evidence required to prove.		
धाराएं 11, 32, 114 एवं 154 – पक्षद्रोही साक्षी – साक्ष्यिक मूल्य।		
– मौखिक मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता।		
– अन्यत्रता का अभिवाक् – साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य।	**137 (i),(iii) & (iv)**	**185**
Sections 21, 58, 101, 102 and 115 – (i) Property of Hindu Undivided Family – Proof of.		
(ii) Admission – Evidentiary value of.		
(iii) Doctrine of election and doctrine of approbate or reprobate .		
धाराएं 21, 58, 101, 102 एवं 115 – (i) हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब की संपत्ति – साबित किया जाना।		
(ii) स्वीकृति – साक्ष्यिक मूल्य।		
(iii) निर्वाचन का सिद्धांत और अनुमोदन या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत।	**307**	**424**
Sections 24 and 30 – (i) Confession; what constitutes? Explained.		
(ii) Confession of a co-accused – When admissible?		
धाराएं 24 एवं 30 – (i) संस्वीकृति; क्या गठित करता है? – व्याख्या की गई।		
(ii) सह–अभियुक्त की संस्वीकृति – कब ग्राह्य है?	**301**	**412**
Section 27 – Recovery of weapon from open field – When reliable?		
धारा 27 – खुले मैदान से हथियार की बरामदगी – कब विश्वसनीय होगी?	**315 (ii)**	**435**
Sections 27 and 106 – Burden of proof and presumption u/s 106 of Evidence Act.		
धाराएं 27 एवं 106 – साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत सबूत का भार एवं उपधारणा।	**41***	**54**
Sections 30 and 114 III. (b) – Confession of co-accused – Evidentiary value.		
धाराएं 30 एवं 114 दृष्टांत (ख) – सह–अभियुक्त की संस्वीकृति – साक्ष्यिक मूल्य।	**84***	**114**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 32 – Dying declaration – Reliability of.		
धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता।	**95***	**135**
Section 32 – See Sections 304-B and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 32 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304–ख एवं 498–क।	**97***	**137**
Sections 32 and 113-B – Multiple dying declarations – Assessment of – Every dying declaration is to be considered independently on its own merit.		
धाराएं 32 एवं 113–ख – एकाधिक मृत्युकालिक कथन – मूल्यांकन – प्रत्येक मृत्युकालिक कथन पर उसके गुण–दोष के अनुसार पृथकतः विचार किया जाना चाहिए।	**264**	**368**
Sections 35, 81 and 114 ill (e) – Revenue Records – Presumption of truth attached to revenue records.		
धाराएं 35, 81 एवं 114 दृष्टांत (ङ) – राजस्व अभिलेख – राजस्व अभिलेखों से संलग्न सत्यता की उपधारणा।	**56 (ii)**	**69**
Section 45 – DNA evidence; nature of. Superimposition test; Evidentiary value.		
धारा 45 – डी.एन.ए. साक्ष्य की प्रकृति। सुपर इंपोजीशन परीक्षण; साक्ष्यिक मूल्य।	**18 (ii) & (iii)**	**25**
Section 45 – Evidentiary value of opinion of Handwriting expert.		
धारा 45 – हस्तलेख विशेषज्ञ की राय का साक्ष्यिक मूल्य।	**257 (i)**	**359**
Section 45 – Handwriting expert – Right to get a document examined.		
धारा 45 – हस्तलेख विशेषज्ञ – किसी दस्तावेज को परीक्षित कराने का अधिकार।	**6 (ii)**	**5**
Section 45 – Opinion of handwriting expert – Evidentiary value.		
धारा 45 – हस्तलिपि विशेषज्ञ का अभिमत – साक्ष्यिक मूल्य।	**201***	**277**
Section 45 – (i) Medical negligence – Determination of – Application of *Bolam's* test. (ii) Expert evidence; evidentiary value of.		
धारा 45 – (i) चिकित्सकीय उपेक्षा का निर्धारण – *बोलम* परीक्षण की प्रयोज्यता। (ii) विशेषज्ञ की साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य।	**302**	**415**
Sections 45, 112 and 114 – (i) Applicability of DNA test in maintenance case. (ii) Effect of refusal by wife for DNA.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 45, 112 एवं 114 – (i) भरण–पोषण के मामले में डी.एन.ए. परीक्षण की प्रयोज्यता। (ii) पत्नी द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण से इंकारी का प्रभाव।	**308**	**427**
Section 53-A – See Sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB and 376E of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 53–क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख एवं 376ङ।	**213**	**294**
Section 58 – Admission – Effect of.		
धारा 58 – स्वीकृति का प्रभाव।	**317 (ii)**	**437**
Section 65 – Secondary evidence; admissibility of.		
धारा 65 – द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता।	**303**	**417**
Section 65-B – Electronic evidence; admissibility of – Reference made to a larger Bench decided.		
धारा 65–ख – इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता – वृहद पीठ को प्रेषित संदर्भ निष्कर्षित किया गया।	**304***	**419**
Section 65-B – See Sections 235 (2) and 354 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 65–ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 235 (2) एवं 354।	**313***	**432**
Section 65-B – Production of electronic evidence during cross-examination.		
धारा 65–बी – प्रतिपरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति।	**202**	**278**
Section 68 – (i) Execution of Will – Whether the scribe of the will can be said to be an attesting witness? (ii) Proof of Will when signature of testator is disputed.		
धारा 68 – (i) वसीयत का निष्पादन – क्या वसीयत का लेखक अनुप्रमाणक साक्षी हो सकता है? (ii) जहां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित हो वहां वसीयत के निष्पादन का साबित किया जाना।	**149**	**209**
Section 68 – Gift deed – Examination of attesting witness – When there is no specific denial of the execution of gift deed.		
धारा 68 – दानपत्र – अनुप्रमाणक साक्षी की परीक्षा – जहां दानपत्र के निष्पादन का कोई विनिर्दिष्ट खण्डन न हो।	**85 (ii)***	**115**
Section 68 – Mode of proof – When execution of document is denied by other party.		
धारा 68 – जब दस्तावेज के निष्पादन को दूसरे पक्ष के द्वारा अस्वीकार किया गया हो तब प्रमाणन की रीति।	**174**	**239**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 83 – Presumption of accuracy of map – Once it is drawn/prepared by Revenue Authorities even when appellate authority sets aside direction for preparation/drawing of such map.		
धारा 83 – राजस्व प्राधिकारियों द्वारा एक बार तैयार किये गये नक्शे की शुद्धता की उपधारणा यहां तक कि जब अपीलीय प्राधिकारी ऐसे नक्शे को तैयार किये जाने के दिशा निर्देश को अपास्त भी कर दे।	**111 (ii)***	**151**
Section 101 – Burden of proof – When both parties come before the court with their pleadings.		
धारा 101 – सबूत का भार – जब दोनों पक्षकार न्यायालय के समक्ष अपने–अपने अभिवचनों के साथ आते है।	**305**	**422**
Sections 101 and 102 – See Sections 34, 38 and 39 of the Specific Relief Act, 1963.		
धाराएं 101 एवं 102 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 34, 38 एवं 39।	**328**	**452**
Section 106 – Facts especially within the knowledge – Burden of proof.		
धारा 106 – विशेषतः ज्ञान का तथ्य – यह साबित करने का भार।	**31***	**40**
Section 106 – Offence committed in secrecy inside house – Initial burden to prove offence is on prosecution and there is a corresponding burden on the inmates of the house to explain how the crime was committed.		
धारा 106 – घर के अंदर एकांत में अपराध कारित किया गया – अपराध साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पर है एवं अपराध कैसे कारित किया गया था, यह स्पष्ट करने का समवर्ती भार घर के सहवासियों पर है।	**154**	**214**
Section 113-A – Conditions which are required to be satisfied to attract the applicability of Section 113-A.		
धारा 113–क – धारा 113–ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिये आवश्यक परिस्थितियां।	**258 (i)**	**360**
Section 113-B – See Sections 302 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 113–ख – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 498–क।	**209**	**285**
Section 114 – See Sections 319 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 114 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।	**193**	**266**
Section 114 – See Section 372 of the Succession Act, 1925 and Section 7 (2) of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धारा 114 – देखें उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 एवं हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 (2)।	**150**	**210**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 138 and 146 – Witness – Right of cross-examination.		
धाराएं 138 एवं 146 – साक्षी – प्रतिपरीक्षण का अधिकार।	**306**	**423**
FOREST ACT, 1927		
वन अधिनियम, 1927		
Section 52 – Release of vehicle – Initiation of confiscation proceedings as well as criminal proceedings for offence relating to forest – Approach.		
धारा 52 – वाहन को छोड़ना – वन से संबंधित अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई – दृष्टिकोण।	**32***	**40**
Sections 52, 52-A, 52-B, 52-C and 53 – See Section 451 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 52, 52–क, 52–ख, 52–ग एवं 53 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 451।	**145**	**197**
Section 68 – Compounding – Denial of releasing the seized vehicle by the competent authority merely on the fact that the accused has admitted his guilt, is not justified.		
धारा 68 – शमन – सक्षम प्राधिकारी द्वारा एकमात्र इस आधार पर जप्त वाहन को छोड़ने से मना करना कि अभियुक्त ने अपनी दोषिता स्वीकार कर ली है, न्यायोचित नहीं है।	**259***	**361**
HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956		
हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956		
Sections 20, 21, 22, 27 and 28 – Maintenance of daughter.		
धाराएं 20, 21, 22, 27 एवं 28 – पुत्री का भरण–पोषण।	**203 (i)**	**279**
HINDU LAW :		
हिन्दू विधि :		
– See Section 7 of the Hindu Marriage Act, 1955.		
– देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7।	**204**	**280**
– See Sections 21, 58, 101, 102 and 115 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 21, 58, 101, 102 एवं 115।	**307**	**424**
HINDU MARRIAGE ACT, 1955		
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955		
Section 7 – Marriage between persons of prohibited degree – In the absence of proof of custom and solemnization of marriage, judicial notice of custom cannot be taken.		
धारा 7 – प्रतिसिद्ध डिग्री के व्यक्तियों के मध्य विवाह – प्रथा अथवा विवाह की सम्पन्नता के सबूत के अभाव में प्रथा के संबंध में न्यायिक अवेक्षा नहीं की जा सकती है।	**204**	**280**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 7 (2) – Presumption of valid marriage – Marriage between two Hindus without *"Saptapadi"* is not a valid marriage.		
धारा 7 (2) – वैध विवाह की उपधारणा – 'सप्तपदी' के बिना दो हिन्दुओं के मध्य सम्पन्न विवाह एक वैध विवाह नहीं है।	**150 (i)**	**210**
Section 9 – Restitution of conjugal rights – Denial of marriage – Effect.		
धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन – विवाह का प्रत्याख्यान – प्रभाव।	**33**	**41**
Sections 11 and 15 – Bar u/s 15 applies only if the appeal is filed within the period of limitation and not after expiry of period of limitation.		
धाराएं 11 एवं 15 – धारा 15 का प्रतिबंध तभी लागू होता है जबकि अपील परिसीमा अवधि के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हो न कि निर्धारित परिसीमा अवधि पश्चात् प्रस्तुत की गई हो।	**260 (i)**	**362**
Section 13 – See Sections 45, 112 and 114 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 13 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 45, 112 एवं 114।	**308**	**427**
Section 13 (1) (ia) – Whether filing a criminal case by one of the spouse and acquittal therein would automatically be treated as a ground of divorce?		
धारा 13 (1) (क) – क्या पति–पत्नी में से एक के द्वारा आपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किया जाना और उसमें दोषमुक्ति हो जाना स्वतः विवाह विच्छेद का आधार है?	**309**	**428**
Sections 13 and 13-B – Divorce – Irretrievable breakdown of marriage – Exercise of power by Supreme Court under Article 142 of the Constitution to dissolve marriage in such cases.		
धाराएं 13 एवं 13–ख – विवाह विच्छेद – विवाह का असुधार्य भंग – ऐसे मामलों में विवाह विघटन के लिये संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग।	**34**	**42**
HINDU MINIORITY AND GUARDIONSHIP ACT, 1956		
हिन्दू अप्राप्तवयता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956		
Sections 7 and 11 – *De-facto* guardian of a Hindu cannot deal with minor's property.		
धाराएं 7 एवं 11 – एक अवयस्क हिंदू का वास्तविक संरक्षक अप्राप्तवय की संपत्ति का सौदा नहीं कर सकता है।	**310**	**429**
HINDU SUCCESSION ACT, 1956		
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956		
Section 8 – (i) Coparcenary property and self-acquired property – Concept of birth right. (ii) Impact on Mitakshara coparcenary – After property is distributed in accordance with Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 8 – (i) सहदायिकी संपत्ति और स्व–अर्जित संपत्ति – जन्मसिद्ध अधिकार की संकल्पना। (ii) मिताक्षरा सहदायिकी पर प्रभाव – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार संपत्ति वितरित होने के पश्चात्।	**35**	**43**
Section 8 – Right of succession of son, born before his father's adoption, from his adopted family's property.		
धारा 8 – पिता के दत्तकग्रहण के पूर्व जन्मे पुत्र का दत्तक परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार।	**151**	**211**
Section 30 – Testamentary succession – Gift deed in favour of stranger – The Burden of proof that the property was ancestral was on the plaintiffs alone.		
धारा 30 – वसीयती उत्तराधिकार – गैर के पक्ष में दानपत्र – यह प्रमाणित करने का भार की सम्पत्ति पैतृक थी अकेले वादीगण पर है।	**85 (i)***	**115**
IDENTIFICATION OF PRISONERS ACT, 1920		
बंदियों की पहचान अधिनियम, 1920		
Section 5 – See Sections 53, 53-A and 311-A of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 5 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 53, 53–क एवं 311–क।	**14**	**18**
INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000		
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000		
Section 2 (1) (t) – See Sections 3 and 65-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 2 (1) (न) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 65–बी।	**215**	**300**
INDIAN PENAL CODE, 1860		
भारतीय दण्ड संहिता, 1860		
Section 29 – See Sections 3 and 65-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 29 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 65–बी।	**215**	**300**
Section 34 – Common intention – Existence of a pre-arranged plan has to be proved – It is not enough to have the "same intention" independently of each other.		
धारा 34 – सामान्य आशय – पूर्व नियोजित योजना का अस्तित्व प्रमाणित करना आवश्यक है – एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से ''समान–आशय'' रखना ही पर्याप्त नहीं है।	**261**	**363**
Sections 34, 149 and 302 – Conversion of conviction from Section 302 r/w/s 149 to one u/s 302 r/w/s 34 – When permissible?		
धाराएं 34, 149 एवं 302 – धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दोषसिद्धि की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन संपरिवर्तन – कब अनुज्ञेय है?	**311**	**429**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 34, 302 and 404 – See Section 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
धाराएं 34, 302 एवं 404 – देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3।	**262**	**364**
Sections 34 and 304 B – Dowry death – Elements to be established.		
धाराएं 34 एवं 304 ख – दहेज हत्या – स्थापित करने हेतु तत्व।	**87 (i)**	**117**
Sections 34, 300 Exception 4, 302 and 304 Part I – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Sudden quarrel.		
धाराएं 34, 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग–एक – हत्या या आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है – अचानक लड़ाई।	**86***	**116**
Section 53 – Sentence – Things to be considered while considering quantum of sentence.		
धारा 53 – दण्ड – दण्ड की मात्रा पर विचार करते समय विचार हेतु अपेक्षित परिस्थितियाँ।	**36***	**46**
Sections 53 and 302 – Death Sentence – Things to be considered while awarding death sentence.		
धाराएं 53 एवं 302 – मृत्यु दण्ड – मृत्यु दण्ड अधिनिर्णित किये जाने के दौरान विचार हेतु अपेक्षित परिस्थितियाँ।	**37 (i)**	**47**
Sections 53, 302 and 304 Part II – (i) Sentence; awarding of – Objectives. (ii) Aggravating and mitigating circumstances – Balance of. (iii) Whether passage of time is a mitigating circumstance in awarding sentence? (iv) Mitigating circumstances – Evaluation of.		
धाराएं 53, 302 एवं 304 भाग–दो – (i) दण्डादेश अधिनिर्णीत किया जाना – उद्देश्य। (ii) गंभीरता बढ़ाने एवं कम करने वाली परिस्थितियाँ – सामंजस्य स्थापित करना। (iii) क्या समय का व्यतीत हो जाना दण्ड के अधिनिर्णयन में गंभीरता कम करने वाली परिस्थिति है? (iv) गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां – निर्धारण।	**88**	**119**
Sections 53, 302, 376 and 376-A – See Section 354 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 53, 302, 376 एवं 376–ए – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354।	**89**	**121**
Section 84 – Plea of unsoundness of mind – When should be raised?		
धारा 84 – विकृतचित्ता का बचाव – कब उठाया जाना चाहिए?	**312 (ii)**	**430**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 86, 302 and 304 – Murder and culpable homicide not amounting to murder – Determination of – Principles reiterated. – General defenses – Intoxication and drunkenness – Attribution of knowledge and intention. **धाराएं 86, 302 एवं 304** – हत्या एवं आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है – विनिश्चय – सिद्धांत दोहराए गए। – सामान्य प्रतिरक्षा – नशा एवं मदिरा पान – ज्ञान और आशय का आरोपण।	**250 (ii) & (iii)**	**345**
Sections 96, 203 and 304 Part-II – Right of private defence – Extent of causing death. **धाराएं 96, 203 एवं 304 भाग–दो** – निज प्रतिरक्षा का अधिकार – मृत्यु कारित करने तक विस्तार।	**90**	**123**
Sections 107 and 306 – (i) To constitute an offence u/s 306 of the IPC, the Prosecution has to establish beyond reasonable doubt that the deceased committed suicide and the accused abetted the commission of suicide. (ii) The mere fact that the applicant has developed some intimacy with co-accused, during subsistence of marriage and failed to discharge her marital obligations, as such would not amount to "cruelty", which drove the deceased to commit suicide. **धाराएं 107 एवं 306** – (i) धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए अभियोजन को ये संदेह से परे स्थापित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की और अभियुक्त ने उसे ऐसी आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया। (ii) केवल यह तथ्य कि विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान आवेदक ने सहअभियुक्त के साथ कुछ अंतरंगता विकसित की और वैवाहिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही। ये ऐसी ''क्रूरता'' नहीं है जो मृतक को आत्महत्या कारित करने में अग्रसर करे।	**248**	**343**
Section 120-B – See Section 239 of the Criminal Procedure Code, 1973. **धारा 120–ख** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 239।	**152**	**211**
Sections 120-B and 302 – Criminal conspiracy – Elements constituting. **धाराएं 120–ख एवं 302** – आपराधिक षड़यंत्र – आवश्यक तत्व।	**76 (i)**	**100**
Sections 120-B, 409 and 477A – FIR (initial complaint) and charge sheet – Difference in quantity of items misappropriated or amount falsified; effect of. **धाराएं 120–ख, 409 एवं 477क** – प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रारंभिक शिकायत) और आरोप पत्र – दुर्विनियोजित संपत्ति की मात्रा एवं खाते में असत्य प्रविष्टि की राशि की मात्रा में भिन्नता; प्रभाव।	**91***	**127**
Sections 120-B, 420, 467, 468, 471 and 477-A – Falsification of account, cheating, forgery and criminal conspiracy – Proof. **धाराएं 120–ख, 420, 467, 468, 471 एवं 477–क** – खाते का मिथ्याकरण, छल, कूटरचना और आपराधिक षड़यंत्र – सबूत।	**92***	**128**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 141, 149 and 300 – Unlawful assembly and murder – Framing of charge – Non-inclusion of Section 141 while framing charges for unlawful assembly – Effect.		
धाराएं 141, 149 एवं 300 – विधि विरूद्ध जमाव और हत्या – आरोप की विरचना – विधि विरूद्ध जमाव के लिये आरोप विरचना में धारा 141 का असमावेश – प्रभाव।	**38**	**48**
Sections 161, 166, 420, 468 and 471 – Cheating and forgery – Conviction and sentence.		
धाराएं 161, 166, 420, 468 एवं 471 – छल एवं कूटरचना – दोषसिद्धि एवं दण्डादेश।	**205**	**281**
Sections 201 and 302 r/w/s 34 – Death sentence – Aggravating and mitigating circumstances.		
धाराएं 201 एवं 302 सहपठित धारा 34 – मृत्युदण्ड – गुरुत्तरकारी तथा लघुत्तरकारी परिस्थितियाँ।	**147 (i) & (ii)**	**202**
Sections 201, 302 r/w/s 34 and 364-A – Case based on circumstantial evidence – Effect of circumstances which do not form a chain.		
धाराएं 201, 302 सहपठित धारा 34 एवं 364–क – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला – ऐसी परिस्थितियों का प्रभाव जो श्रृंखला को पूर्ण नहीं करती है।	**153**	**212**
Sections 279, 304-A, 337 and 338 – See Sections 183 and 184 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
धाराएं 279, 304–क, 337 एवं 338 – देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 183 एवं 184।	**166**	**229**
Sections 300, 302 and 304 Part II – Occurrence took place suddenly and there was no premeditation on the part of the accused – Culpable homicide not amounting to murder.		
धाराएं 300, 302 एवं 304 भाग–दो – जहां घटना अभियुक्त के भाग पर पूर्व चिंतन के बिना अचानक होती है – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध।	**93 (i)**	**128**
Section 302 – Capital punishment – When may be awarded?		
धारा 302 – मृत्यु दण्डादेश – कब अधिनिर्णित किया जा सकता है?	**39**	**49**
Section 302 – Death sentence – Imposition of, in cases based on circumstantial evidence.		
धारा 302 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में मृत्यु दण्ड का अधिरोपण।	**40**	**51**
Section 302 – Explanation by accused – In a case of unnatural death inside a house, when prosecution establishes its case *prima facie*, then the accused is obliged to furnish some explanation u/s 313 CrPC.		
धारा 302 – अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण – घर के भीतर हुई एक अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में, जब अभियोजन प्रथम दृष्टया अपने मामले को स्थापित कर देता है तब अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उन परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने हेतु बाध्य है।	**206**	**282**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 302 – Murder of wife – Knowledge and intention.		
धारा 302 – पत्नी की हत्या – ज्ञान एवं आशय।	**207**	**283**
Section 302 – See Sections 3 and 45 of the Evidence Act, 1872 and Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 45 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154।	**94**	**131**
Section 302 – See Sections 27 and 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 27 एवं 106।	**41***	**54**
Section 302 – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	**95***	**135**
Section 302 – See Section 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106।	**154**	**214**
Section 302 r/w/s 149 – Murder – Unlawful assembly – Common object – May be gathered from the course of conduct adopted by the members of the assembly, nature of assembly, arms carried by members and behaviour of members at or near the scene of incident.		
धारा 302 सहपठित धारा 149 – हत्या – विधि विरुद्ध जमाव – सामान्य उद्देश्य – जमाव के सदस्यों द्वारा किए गए आचरण, जमाव के स्वरूप, सदस्यों द्वारा धारित हथियार एवं घटना स्थल पर या उसके समीप सदस्यों द्वारा किए जा रहे व्यवहार के आधार पर गठित किया जा सकता है।	**208**	**284**
Sections 302 and 304 – See Sections 2(k) and 7-A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.		
धाराएं 302 एवं 304 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराएं 2(ट) एवं 7–क।	**42**	**55**
Sections 302 and 304 Part II – Murder or culpable homicide not amounting to murder.		
धाराएं 302 एवं 304 भाग–दो – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध।	**96**	**135**
Sections 302 and 304 Part II – Murder and culpable homicide not amounting to murder.		
धाराएं 302 एवं 304 भाग II – हत्या और आपराधिक मानव वध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है।	**137 (v)**	**185**
Sections 302 and 376-AB – See Section 9 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 302 एवं 376–कख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9।	**263**	**366**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 302, 363, 376 and 377 – Rape and murder – Sentence – Application of doctrine of proportionality.

धाराएं 302, 363, 376 एवं 377 – बलात्संग एवं हत्या – दण्डादेश – समानुपात के सिद्धांत का लागू होना। **148 (ii) 207**

Sections 302 and 364 – See Sections 154 and 173 (8) of the Criminal Procedure Code, 1973 and Section 45 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 302 एवं 364 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 173 (8) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45। **18 25**

Sections 302 and 364 – See Sections 235 (2) and 354 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 302 एवं 364 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 235 (2) एवं 354। **313 432**

Sections 302 and 376 (2) (i) (As inserted by Amendment Act of 2013) – Rape and murder – Subsequent conduct of accused – Cause of death – Expert evidence – DNA report – Plea of alibi – Sentence.

धाराएं 302 एवं 376 (2) (i) (2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अन्तः स्थापित) – बलात्कार और हत्या – अभियुक्त का पश्चातवर्ती आचरण – मृत्यु का कारण – विशेषज्ञ साक्ष्य – डीएनए प्रतिवेदन – अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् – दण्डादेश। **210 287**

Sections 302 and 392 r/w/s 34 – Circumstantial evidence – Facts must be such which do not admit any inference but of guilt – Absence of test identification parade, but reliable testimony of witness – Effect.

धाराएं 302 एवं 392 सहपठित धारा 34 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – तथ्य ऐसे होने चाहिए जो दोषिता के अतिरिक्त किसी अनुमान को अनुज्ञात नहीं करते हो – पहचान परेड की अनुपस्थिति परन्तु साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य – प्रभाव। **43* 57**

Sections 302 and 394 – See Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Sections 9 and 45 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 302 एवं 394 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 9 एवं 45। **136 182**

Sections 302 and 498-A – Dowry death and cruelty – Existence of presumption.

धाराएं 302 एवं 498–क – दहेज मृत्यु और क्रूरता – उपधारणा का अस्तित्व। **209 285**

Sections 302 and 498-A – See Sections 273 and 317 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 302 एवं 498–क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 273 एवं 317। **314 434**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 302 r/w/s 34 – See Section 15(1)(g) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

धारा 302 सहपठित धारा 34 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15(1)(छ)। **155** **215**

Section 304 – See Section 2 (33) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

धारा 304 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(33)। **157** **217**

Section 304 Part I – Culpable homicide not amounting to murder – Exception 4 to Section 300 IPC is attracted only when there is a fight or quarrel which requires mutual provocation and blows by both sides in which the offenders does not take undue advantage.

धारा 304 भाग 1 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 का अपवाद 4 केवल तब प्रभावी होता है जब कोई लड़ाई या झगड़ा दोनों ही पक्षों के पारस्परिक प्रकोपन और आद्योतों से हुआ हो, जिसमें अपराधियों द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है। **211** **292**

Sections 304-B and 498-A – Cruelty and Dowry Death – Presumption.

धाराएं 304–ख एवं 498–क – क्रूरता एवं दहेज मृत्यु – उपधारणा। **101*** **142**

Section 304-B – Dowry death – "Soon before her death" – Consideration of.

धारा 304–ख – दहेज मृत्यु – ''उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व'' – विचारणीय पद। **44** **57**

Sections 304-B and 498-A – Dowry death and cruelty – Contradictory statements made by victim in two dying declarations – effect.

धाराएं 304–ख एवं 498–क – दहेज मृत्यु एवं क्रूरता – दो मृत्युकालीन कथनों में आहत द्वारा विरोधाभाषी कथन किए गए हैं – प्रभाव। **97*** **137**

Sections 304-B and 498-A – See Sections 32 and 113-B of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 304–ख एवं 498–क – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 एवं 113–ख। **264** **368**

Section 306 – See Sections 227 and 397 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 306 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 227 एवं 397। **140** **193**

Sections 306 and 498-A – Absence of physical or mental cruelty.

धाराएं 306 एवं 498–क – मानसिक अथवा शारीरिक क्रूरता का अभाव। **45*** **59**

Sections 306 and 498-A – Merely because an accused is found guilty of an offence punishable under Section 498-A of the Code and the death has occurred within a period of seven years of marriage, accused cannot be automatically held guilty for offence

punishable u/s 306 of the Code by employing the presumption under Section 113-A of the Act – Unless prosecution establishes that some act of illegal omissions by the accused has driven the deceased to commit suicide, conviction u/s 306 of the Code would not be tenable.

धाराएं 306 एवं 498–क – केवल इस कारण कि एक अभियुक्त संहिता की धारा 498–ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया और मृत्यु विवाह से सात वर्ष के भीतर कारित हुई, अभियुक्त स्वतः ही संहिता की धारा 113–ए की उपधारणा करते हुए संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता – जब तक अभियोजन यह स्थापित नहीं करता कि अभियुक्त द्वारा किये गये किसी अवैध लोप के कृत्य ने मृतका को आत्महत्या कारित करने हेतु प्रेरित किया, संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। **258 (ii) 360**

Section 307 – See Sections 27 of the Evidence Act, 1872.

धारा 307 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27। **315 435**

Section 307 r/w/s 149 – Attempt to murder – Unlawful assembly – Determination of vicarious liability – Merely because other three accused persons had not used their weapons does not absolve them from the responsibility and vicarious liability.

धारा 307 सहपठित धारा 149 – हत्या का प्रयास – विधि विरुद्ध जमाव – प्रतिनिहित दायित्व का निर्धारण – केवल इस कारण से कि अन्य तीन अभियुक्तगण द्वारा अपने हथियारों का उपयोग नहीं किया गया उन्हें प्रतिनिहित दायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं करता है। **212 293**

Section 364-A – Kidnapping for ransom – Circumstantial evidence.

धारा 364–क – मुक्तिधन के लिये व्यपहरण – परिस्थितिजन्य साक्ष्य। **98 138**

Sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB and 376E – (i) Crime against women – Malady and remedy.

(ii) Rape cases in India – Need for speedy trial of cases relating to offence of rape as emphasized consistently by the Supreme Court.

(iii) Compensation to the victims of sexual offences – On recommendation of Court.

धाराएं 376, 376क, 376कख, 376ख, 376ग, 376घ, 376घक, 376घख एवं 376ङ –

(i) महिलाओं के विरूद्ध अपराध – व्याधि एवं उपचार।

(ii) भारत में बलात्कार प्रकरण – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारम्बार बलात्कार के अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र विचारण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(iii) न्यायालय की अनुशंसा पर यौन अपराध की पीड़िता को प्रतिकर। **213 294**

Section 376 (1) (before 2013 amendment) r/w/s 34 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.

धारा 376(1) (2013 के संशोधन से पूर्व) सहपठित धारा 34 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3। **214* 299**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 376 (1) – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 376 (1) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	**156**	**216**
Section 376 (2)(1) (Prior to Amendment 2013) – Rape – Appreciation of evidence.		
धारा 376 (2)(1) (2013 के संशोधन से पूर्व) – बलात्कार – साक्ष्य का मूल्यांकन।	**99***	**141**
Sections 406 and 420 – Cheating – Allurement of large number of investors for deposit – Whether each deposit constitute a separate and individual offence or all transactions can be clubbed into single FIR?		
धाराएं 406 एवं 420 – छल – निक्षेप के नाम पर बड़ी संख्या में निवेशकों को प्रलोभन – क्या प्रत्येक निक्षेप एक पृथक और व्यक्तिगत अपराध का गठन करता है अथवा सभी लेनदेन को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में जोड़ा जा सकता है?	**46 (i)**	**59**
Sections 409, 420 and 511 – See Section 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 409, 420 एवं 511 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 228।	**72***	**96**
Sections 419, 420, 467, 468 and 471 – See Section 300 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 419, 420, 467, 468 एवं 471 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300।	**249***	**344**
Section 494 – Whether applies to male belonging to Muslim community?		
धारा 494 – क्या मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले पुरूष पर लागू होती है?	**100***	**141**
Sections 498-A and 302 – (i) Circumstantial evidence – Bride burning.		
(ii) Witnesses turning hostile – Effect.		
धाराएं 498–क एवं 302 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – वधु दाह।		
(ii) साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाना – प्रभाव।	**47**	**61**
INTERPRETATION OF STATUTES:		
संविधियों का निर्वचनः		
– Two conflicting provisions of same statute – Principles of interpretation.		
– एक ही विधि के दो विराधाभासी प्रावधान – निर्वचन के सिद्धांत।	**316***	**436**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000		
Sections 2(k) and 7-A – Age determination – Claim of juvenility on the date of incident i.e. 18.06.1995 on the basis of birth certificate obtained on 14.09.2010.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 2(ट) एवं 7—क – आयु का निर्धारण – दिनांक 14.09.2010 को प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर घटना दिनांक 18.06.1995 को किशोरवयता का दावा।	**42**	**55**
Section 7-A – Age determination – Claim of juvenility.		
धारा 7—क – आयु निर्धारण – किशोरवयता का दावा।	**265***	**370**
Section 15 (1) (g) – Plea regarding juvenility can be raised even at the appellate stage.		
धारा 15 (1) (छ) – किशोरवयता के संबंध में अभिवाक् अपील के स्तर पर भी उठाया जा सकता है।	**155**	**215**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015		
Section 2 (33) – Heinous offence – Offence where maximum sentence is more than 7 years imprisonment, but no minimum sentence or minimum sentence of less than 7 years is provided shall be treated as 'serious offences' within the meaning of the Act.		
धारा 2 (33) – जघन्य अपराध – अपराध जहां कि अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास की है किंतु कोई न्यूनतम दण्डादेश नहीं है या 7 वर्ष से कम का न्यूनतम दण्डादेश उपबंधित किया गया है, वह अधिनियम के अर्थान्वयन के अंतर्गत गंभीर अपराध माने जाएगें।	**157**	**217**
Sections 8, 10 and 12 – Applicability of Sections 437 and 439 on bail application of Juvenile.		
धाराएं 8, 10 एवं 12 – किशोर के जमानत आवेदन पर धाराएं 437 और 439 का लागू होना।	**80***	**107**
Sections 58 and 59 – Adoption – Change in citizenship during pendency of application; effect of.		
धाराएं 58 एवं 59 – दत्तक ग्रहण – आवेदन के लंबित रहने के दौरान नागरिकता में परिवर्तन; प्रभाव।	**102***	**142**
LAND ACQUISITION ACT, 1894		
भू—अर्जन अधिनियम, 1894		
Section 23 – Compensation – Determination of – Annual increase method.		
धारा 23 – प्रतिकर – निर्धारण – वार्षिक वृद्धि पद्धति।	**103***	**143**
Sections 23, 28, 34 and 54 – Condonation of delay in filing appeal – Appellant is not entitled to interest for period of delay in filing appeal.		
धाराएं 23, 28, 34 एवं 54 – अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना – अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।	**266**	**371**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)

Section 158 (1) (d) (i) – Bhumiswami Right to Pattedar-tenant in Vindhya Pradesh.

धारा 158 (1) (घ) (एक) – विंध्य प्रदेश के पट्टेदार–किरायेदार को भूमिस्वामी अधिकार। **317 (i)** **437**

Section 178 – See Order 22 Rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 178 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 22 नियम 3। **65** **89**

LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

– Award by playing fraud – Any award of Lok Adalat which is obtained by playing fraud is *void ab intio*.

– कपट से प्राप्त अधिनिर्णय – लोक अदालत द्वारा पारित कोई अधिनिर्णय जो कि कपटपूर्वक प्राप्त किया गया हो, वह आरंभतः शून्य है। **216** **306**

Section 19 – See Sections 138 and 147 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

धारा 19 – देखे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 147। **274*** **378**

LIMITATION ACT, 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 5 – (i) Appellate Court; duty of – Whether appellate Court is duty bound to consider all the issues and evidence on record even though appeal is barred by limitation?

(ii) Condonation of delay – Sufficient cause – Grounds raised by appellants that they were not aware of the dismissal of suit.

धारा 5 – (i) अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य – क्या अपीलीय न्यायालय परिसीमा द्वारा वर्जित अपील में भी समस्त विवाद्यकों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है?

(ii) विलंब क्षमा किया जाना – पर्याप्त हेतुक – अपीलार्थीगण द्वारा यह आधार लिया गया कि उन्हें वाद की खारिजी की जानकारी नहीं थी। **48** **63**

Section 5 – Condonation of delay – In absence of any explanation of delay, the Court should not adopt a lenient view.

धारा 5 – विलंब के लिये माफी – अस्पष्टीकृत विलंब की माफी पर न्यायालय को उदारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। **125** **168**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 5 – Extension of time or condonation of delay u/s 5 of the Act is not applicable to the proceedings under Order 21 Rule 90 of the Code.		
धारा 5 – सि.प्र.सं. के आदेश 21 नियम 90 के अंतर्गत कार्यवाहियों में अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा या समय का विस्तार नहीं किया जा सकता है।	**318**	**440**
Section 5 – See Section 96 and Order 41 Rule 23 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 5 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 23।	**62**	**85**
Section 19 r/w/ Article 113 – Limitation law – Exemption from – When can be permitted?		
धारा 19 सहपठित अनुच्छेद 113 – परिसीमा विधि से छूट – कब अनुज्ञात की जा सकती है?	**183 (i)**	**251**
Section 27 – Adverse Possession; meaning, nature and ingredients of – Reiterated.		
धारा 27 – प्रतिकूल कब्जा; अर्थ, प्रकृति और तत्व, दोहराए गए।	**104**	**144**
Section 27 and Article 58 – (i) Adverse possession – Possession given under invalid sale deed.		
(ii) Different cause of action accrues on different dates – Article 58 would govern only the suit for the relief of declaration and it will not cover other relief governed by other articles of the Limitation Act.		
धारा 27 एवं अनुच्छेद 58 – (i) प्रतिकूल आधिपत्य – अविधिमान्य विक्रय विलेख के आधार पर कब्जा प्रदान किया गया।		
(ii) भिन्न वाद कारण भिन्न दिनांको को प्रोद्भुत हुए – अनुच्छेद 58 से केवल घोषणा की सहायता के लिए प्रस्तुत वाद शासित होगा और यह परिसीमा अधिनियम के अन्य अनुच्छेदों से शासित होने वाली सहायता पर आच्छादित नहीं होगा।	**105***	**145**
Section 27, Articles 64 and 65 – Adverse possession – Person perfecting title by virtue of adverse possession can maintain suit under Article 65.		
धारा 27, अनुच्छेद 64 एवं 65 – प्रतिकूल आधिपत्य – प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है।	**49**	**64**
Article 54 – Specific performance of contract – Limitation to file suit – When specific date fixed for execution of sale deed in agreement.		
अनुच्छेद 54 – अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुपालन – वाद संस्थित करने का परिसीमा काल – जब अनुबंध में विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि नियत की गई थी।	**113 (i)**	**153**
Articles 58 and 59 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
अनुच्छेद 58 एवं 59 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	**286**	**393**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Article 59 – Limitation period for challenging registered sale deed.		
अनुच्छेद 59 – पंजीकृत विक्रय विलेख की चुनौती देने के लिये परिसीमा अवधि।	**3* (i)**	**2**
Article 61 (a) – Computation of limitation for suit for Redemption of usufructuary mortgage.		
अनुच्छेद 61 (क) – भोगबंधक के मोचन के दावे के लिए परिसीमा की गणना।	**176**	**242**
Article 65 – Adverse possession – Defendants have not admitted vesting of suit property with current and previous owners and denied title of both.		
अनुच्छेद 65 – विरोधी आधिपत्य – प्रतिवादीगण ने विवादित सम्पत्ति वर्तमान तथा पूर्व स्वामी को निहित होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया एवं दोनों के स्वामित्व से इंकार किया हो।	**217***	**307**
Article 65 – Plaintiff, can claim title based on adverse possession.		
अनुच्छेद 65 – वादी, प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का दावा कर सकता है।	**56 (i)**	**69**
Article 97 – Limitation – When a specific provision for limitation is provided under Limitation Act for filing a civil suit, then general provisions of limitation for declaration of suit will not be applicable.		
अनुच्छेद 97 – परिसीमा – जब परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सिविल वाद प्रस्तुत करने हेतु विशिष्ट प्रावधान दिया गया है तब घोषणा के लिए प्रस्तुत वाद की परिसीमा हेतु उल्लेखित सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे।	**232 (ii)**	**329**
Article 136 – Limitation to file execution petition of arbitral award.		
अनुच्छेद 136 – माध्यस्थम् पंचाट के निष्पादन की याचिका दायर किए जाने हेतु परिसीमा।	**118**	**159**
MEDICAL NEGLIGENCE:		
चिकित्सकीय उपेक्षाः		
– See Section 45 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45।	**302**	**415**
MITAKSHARA LAW:		
मिताक्षरा विधि :		
– See Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956.		
– देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8।	**35**	**43**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
MOTOR VEHICLES ACT, 1988		
मोटरयान अधिनियम, 1988		
Section 2 (30) – (i) Whether registered owner or financier has to be treated as "owner" – Guiding factors.		
(ii) Calculation of income – Deduction.		
धारा 2 (30) – (i) पंजीकृत स्वामी अथवा फाइनेन्सर में से किसे स्वामी माना जाए – मार्गदर्शक सिद्धान्त।		
(ii) आय की गणना – कटौती।	**158***	**220**
Sections 2 (30) and 168 – Motor accident claim – Liability of Government to pay compensation – Death of victim due to rash and negligent driving of bus of State Road Transport.		
धाराएं 2 (30) एवं 168 – मोटर दुर्घटना दावा – मुआवजे के भुगतान का सरकार का दायित्व – राज्य सड़क परिवहन की बस को उपेक्षापूर्वक और लापरवाही से चलाने के कारण पीड़ित की मृत्यु।	**106***	**146**
Section 147 (1) – Act policy – Although Act policy does not cover the occupant of the car or the pillion rider but if the Insurance Company takes additional premium for passengers then it means that the gratuitous passengers are insured by the Insurance Company.		
धारा 147 (1) – एक्ट पॉलिसी – हालांकि एक्ट पॉलिसी कार के अधिभोगी या पीछे की सीट की सवारी को शामिल नहीं करती किंतु यदि बीमा कंपनी यात्रियों के लिये अतिरिक्त राशि लेती है तो इसका अर्थ यह है कि निःशुल्क यात्री बीमा कंपनी द्वारा बीमित हैं।	**267**	**371**
Section 147 (1) – Breach of policy – Liability of Insurance Company.		
धारा 147 (1) – संविदा का भंग – बीमा कंपनी का दायित्व।	**159**	**220**
Section 147 (1)(b)(i) – Pay and recover – Fundamental breach of policy condition.		
धारा 147 (1)(ख)(i) – भुगतान करो और वसूलो – पालिसी की शर्तो का आधारभूत उल्लंघन।	**160**	**221**
Section 149 (2)(a)(i)(c) – Permit – Liability of Insurance Company.		
धारा 149 (2)(क)(i)(ग) – अनुज्ञापत्र – बीमा कंपनी का दायित्व।	**161**	**222**
Section 149 (2)(a)(i)(c) – Violation of policy – Insurance company is liable to satisfy the award and thereafter, seek recovery from the owner of the vehicle if the offending vehicle was not having permit and fitness certificate on the date of accident.		
धारा 149 (2)(क)(i)(ग) – पालिसी का उल्लंघन – यदि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन का परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था तो बीमा कंपनी प्रतिकर प्रदान करने के लिये जिम्मेदार हैं और उसके पश्चात् मालिक से वसूली कर सकती है।	**268**	**372**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 163-A – Borrower of vehicle – Liability of Insurance Company.		
धारा 163–क – वाहन को मांगकर चलाने वाला व्यक्ति – बीमा कंपनी का दायित्व।	**162**	**223**
Section 163-A – (i) Motor accident claim – assessment of income of deceased. (ii) When deceased is unmarried – Multiplier should be applied on the age of deceased.		
धारा 163–ए – (i) मोटर दुर्घटना दावा – मृतक की आय का आंकलन। (ii) जब मृतक अविवाहित हो – मृतक की आयु पर गुणांक प्रयोज्य होना चाहिए।	**52***	**67**
Section 163-A – Permanent disability – Determination of compensation.		
धारा 163–ए – स्थाई निःशक्तता – क्षतिपूर्ति का निर्धारण।	**53***	**67**
Sections 163-A and 166 – Assessment of compensation – (i) Death of housewife – Notional income – Future prospects; entitlement of. (ii) Death of school going child – Future prospects; entitlement of.		
धाराएं 163–क एवं 166 – प्रतिकर का निर्धारण – (i) गृहिणी की मृत्यु – काल्पनिक आय – भविष्यवर्ती लाभ; पात्रता। (ii) स्कूल जाने वाले बच्चे की मृत्यु – भविष्यवर्ती लाभ; पात्रता।	**319**	**441**
Section 166 – (i) Compensation – Enhancement – Injury claim. (ii) Liability of insurer – Principle of pay and recover.		
धारा 166 – (i) क्षतिपूर्ति – वृद्धि – उपहति दावा। (ii) बीमाकर्ता का दायित्व – भुगतान एवं वसूली का सिद्धांत।	**107***	**146**
Section 166 – Compensation – Multiplier – Multiplier has to be applied on the basis of age of the deceased and not on the basis of age of the dependants.		
धारा 166 – क्षतिपूर्ति – गुणांक – मृतक की आयु के आधार पर गुणांक प्रयोज्य किया जाना चाहिए ना कि आश्रितों की आयु के आधार पर।	**50**	**65**
Section 166 – (i) Future prospects should also be awarded in case of self employed person. (ii) Interest from the date of filing of the claim till the payment of the amount may be awarded.		
धारा 166 – (i) स्वनियोजित कर्मचारी के मामले में भी भविष्यवर्ती लाभ अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए। (ii) याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से राशि के भुगतान तक ब्याज अधिनिर्णीत किया जा सकता है।	**163**	**224**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 166 – (i) Just compensation. (ii) Quantum of compensation. (iii) Notional Income. (iv) Assessment of compensation – In cases of 100% physical disability coupled with mental disability. (v) Interest – If on account of negligence of claimant, the decision of the case is delayed.		
धारा 166 – (i) न्यायसंगत प्रतिकर। (ii) प्रतिकर की मात्रा। (iii) काल्पनिक आय। (iv) 100 प्रतिशत शारीरिक अक्षमता के साथ–साथ मानसिक अक्षमता के प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण। (v) ब्याज – यदि दावेदार की उपेक्षा के कारण प्रकरण के निर्णय में विलंब हुआ हो।	**164**	**224**
Section 166 – Income tax return – Where income tax return is available, determination of agricultural income must proceed on the basis of income tax return.		
धारा 166 – आयकर रिटर्न – जहाँ आयकर रिटर्न उपलब्ध है, वहां कृषि आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर ही आंकलित किया जाना चाहिए।	**218**	**309**
Section 166 – Multiplier and loss of consortium.		
धारा 166 – गुणांक एवं साहचर्य की हानि।	**165**	**227**
Section 166 – Claim application – If claimant fails to prove that proximate cause of death was road accident and there was nexus between injuries and death, rejection of claim application by Tribunal is justified.		
धारा 166 – दावा आवेदन – जब दावेदार यह साबित करने में असफल रहता है कि मृत्यु का आसन्न कारण सड़क दुर्घटना थी तथा चोटों और मृत्यु के बीच संबंध था, तब अधिकरण द्वारा दावा आवेदन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।	**320**	**443**
Sections 166 and 168 – Compensation – Computation of – Fellowship component should not be excluded while computing compensation in motor accident claim cases.		
धाराएं 166 एवं 168 – प्रतिकर – संगणना – मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में प्रतिकर की संगणना करते हुए अध्येतावृत्ति घटक को अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए।	**51**	**66**
Sections 166 and 168 – Compensation – Future prospects – In computation of compensation, future prospects of the self-employed person (deceased) must be considered according to his age at the time of accident.		

धाराएं 166 एवं 168 – प्रतिकर – भावी आय – प्रतिकर की गणना में स्वनियोजित व्यक्ति (मृत) की भावी आय हेतु दुर्घटना के समय उसकी उम्र के आधार पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। **270*** **374**

Sections 166 and 168 – (i) Compensation – Income reduced by tax benefit on LIC investments cannot be construed to be loss of income of assessee.

(ii) Loss of income – Merely running of shop by the L.Rs. of the deceased by itself shall not lead to presumption of no loss of income to the family.

धाराएं 166 एवं 168 – (i) प्रतिकर – एल.आई.सी. में निवेश पर कर लाभ द्वारा कम की गई आय को आंकलनकर्ता की आय का नुकसान नहीं माना जा सकता है।

(ii) आय की हानि – मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा मृतक की दुकान चलाया जाना मात्र स्वतः ही परिवार की आय की कोई हानि न होने की उपधारणा नहीं है। **269** **373**

Sections 166 and 168 – (i) Compensation – Liability – Once in a claim petition filed by the other claimant arising out of the same accident, it has been held that Insurance Company is liable to indemnify the owner and is jointly and severally liable to pay compensation, then the said finding would be binding unless any new evidence is led by the parties.

(ii) Abatement – Non-bringing of legal representatives of the deceased driver of the offending vehicle do not affect the petition adversely and it does not result in abatement of the claim petition in *toto*.

धाराएं 166 एवं 168 – (i) प्रतिकर – उत्तरदायित्व – एक ही दुर्घटना से उत्पन्न अन्य दावेदार द्वारा दायर दावा याचिका में जब एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि बीमा कंपनी मालिक को क्षतिपूर्ति हेतु दायी है और वह प्रतिकर भुगतान हेतु संयुक्ततः व पृथकतः रूप से उत्तरदायी है तब उक्त निष्कर्ष बाध्यकारी होगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिया जाये।

(ii) उपशमन – उल्लंघनकर्ता वाहन के मृत चालक के विधिक प्रतिनिधियों को न लाना याचिका को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करता और इसके परिणामतः याचिका का पूर्णतः उपशमन नहीं हो जाता। **271*** **375**

Sections 166 and 168 – Contributory negligence – Whether principle of contributory negligence is always applicable where two-wheeler vehicle is driven with more than permissible limits of pillion riders? No.

धाराएं 166 एवं 168 – अंशदायी उपेक्षा – क्या पिछली सीट पर अनुज्ञेय सीमा से अधिक सवारी होने पर अंशदायी उपेक्षा का सिद्धांत सदैव लागू होता है? नहीं। **219** **309**

Sections 166 and 168 – Whether a driver who has a license to drive a light motor vehicle and is driving a transport vehicle of that class is required to additionally obtain an endorsement to drive a transport vehicle?

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 166 एवं 168 – क्या एक चालक जिसके पास एक हल्का मोटर वाहन, चलाने की अनुज्ञप्ति है और उसी वर्ग का परिवहन वाहन चला रहा है, के लिए अतिरिक्त रूप से परिवहन वाहन चलाने का पृष्ठांकन प्राप्त करना आवश्यक है?	**108***	**147**
Sections 166 and 173 – Compensation – Computation of income – Consideration of latest ITRs.		
धाराएं 166 एवं 173 – प्रतिकर – आय की गणना – नवीनतम आयकर विवरणी पर विचार।	**321***	**445**
Section 168 – Motor Insurance – Commercial Vehicle package policy – Effect of delay in intimating the insurance company about the occurrence of the theft.		
धारा 168 – वाहन बीमा – वाणिज्यिक यान पैकेज पालिसी – चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी का प्रभाव।	**272***	**376**
Section 173 – See Civil Practice		
धारा 173 – देखें सिविल प्रथा	**231**	**328**
Section 173 – See Order 41 Rule 22 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 173 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 22।	**273**	**376**
Sections 183 and 184 – Motor Vehicles Act and Indian Penal Code operate in entirely different spheres – An offender can be tried and punished independently under both the statutes.		
धाराएं 183 एवं 184 – मोटरयान अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता पूर्णतः अलग–अलग क्षेत्रों में प्रवर्तित हैं – एक अपराधी दोनों विधियों के अंतर्गत स्वतंत्रतापूर्वक विचारित एवं दण्डित किया जा सकता है।	**166**	**229**
N.D.P.S. ACT, 1985		
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985		
Sections 18 and 50 – (i) Search and seizure – Compliance of Section 50 when not required?		
(ii) Production of entire contraband before court – When not necessary?		
धाराएं 18 एवं 50 – (i) तलाशी एवं जप्ती – धारा 50 का अनुपालन कब आवश्यक नहीं?		
(ii) न्यायालय के समक्ष संपूर्ण निषिद्ध पदार्थ की प्रस्तुति – कब आवश्यक नहीं?	**322**	**445**
Section 21 (as amended by Amendment Act 9 of 2001) – Determination of quantity – In case of seizure of mixture of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances with one or more neutral substance(s), the quantity of neutral substance(s) is not to be excluded and to be taken into consideration along with actual content by weight of the offending drug.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 21 (वर्ष 2001 के अधिनियम क्रमांक 9 द्वारा यथा संशोधित) – मात्रा का निर्धारण – एक या अधिक उदासीन पदार्थ के साथ अभिगृहीत स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के मिश्रण में से उदासीन पदार्थ की मात्रा को अपवर्जित नहीं किया जा सकता और उसे प्रश्नगत औषधि की मात्रा के साथ विचार में लिया जावेगा।	**323**	**447**
Section 37 – (i) Bail – NDPS Act – Restrictions and limitations. (ii) "Reasonable grounds" occurring in Section 37 of the 1985 Act – Connotation of. **धारा 37** – (i) जमानत – स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम – प्रतिबंध एवं सीमाएं। (ii) 1985 के अधिनियम की धारा 37 में प्रयुक्त ''युक्तियुक्त आधार'' – तात्पर्य।	**255**	**357**
Section 50 – Personal search – The mandate of Section 50 of the Act is confined to "personal search" and not to search of a vehicle or container or premises. **धारा 50** – व्यक्तिगत तलाशी – धारा 50 का आदेश व्यक्तिगत तलाशी तक सीमित है और यह किसी वाहन की अथवा पात्र अथवा प्रांगण की तलाशी पर लागू नहीं होते है।	**220**	**310**
Section 57 – (i) Section 57 of N.D.P.S. Act – Not to be interpreted that if report is not sent within two days, the entire proceeding shall be vitiated. (ii) Seizure memo – Mere fact that one seal on seizure memo was illegible, does not vitiate the entire proceeding. **धारा 57** – (i) एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि दो दिनों के भीतर वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाएगी। (ii) जप्ती पंचनामा – मात्र यह तथ्य कि जप्ती पंचनामे पर लगी हुई सीलों में से एक सील अस्पष्ट/अपठनीय थी, सम्पूर्ण कार्यवाही को दूषित नहीं करता।	**324**	**448**
NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 **परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881**		
Sections 118 (a), 138 and 139 – Effect of presumption when issuance of cheque is admitted/established. **धाराएं 118 (क) 138 एवं 139** – उपधारणा का प्रभाव जब चेक का जारी होना स्वीकृत/स्थापित हो जाता है।	**257 (ii)**	**359**
Section 138 – No prohibition u/s 138 on instituting criminal complaint based on the second or successive statutory notice. **धारा 138** – द्वितीय या पश्चातवर्ती वैधानिक सूचना पत्र के आधार पर धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक परिवाद संस्थित करने में कोई प्रतिषेध नहीं है।	**167**	**230**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 138 – See Section 427 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 138 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427।	**25**	**36**
Section 138 – What amount should be mentioned in demand notice issued u/s 138?		
धारा 138 – धारा 138 के अधीन जारी मांग सूचनापत्र में किस राशि का उल्लेख होना चाहिए?	**54***	**68**
Sections 138, 118(a) and 139 – (i) Initial burden. (ii) Discharge of onus – Onus to establish a probable defence shifts on the accused to rebut such presumption.		
धाराएं 138, 118(क) एवं 139 – (i) प्रारंभिक भार। (ii) दायित्व का उन्मोचन – तदोपरांत अभियुक्त पर दायित्व अंतरित होता है कि वह अधिसंभाव्य प्रतिरक्षा स्थापित करे जिससे ऐसी उपधारणा का खंडन हो।	**221**	**311**
Sections 138 and 139 – Dishonour of cheque – Presumption.		
धाराएं 138 एवं 139 – चेक का अनादरण – उपधारणा।	**109**	**148**
Sections 138 and 139 – Standard of proof required to rebut the presumption of existence of legally enforceable debt.		
धाराएं 138 एवं 139 – विधितः प्रवर्तनीय ऋण के अस्तित्व की उपधारणा का खण्डन करने के लिए आवश्यक प्रमाण का स्तर।	**168**	**232**
Sections 138 and 139 – Presumption of existence of legally enforceable debt/liability and liability of accused to rebut such presumption by leading evidence.		
धाराएं 138 एवं 139 – विधिक रूप से प्रवर्तनीय उत्तरदायित्व/ऋण के विद्यमान होने की उपधारणा और अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ऐसी उपधारणा के खंडन करने का उत्तरदायित्व।	**169**	**233**
Sections 138 and 143-A (5) (as inserted by Amendment Act 20 of 2018) – Provisions of Section 143-A are prospective in operation and can be invoked only in cases where offence u/s 138 was committed after its introduction.		
धाराएं 138 एवं 143–क (5) (2018 के 20 संशोधन अधिनियम, द्वारा अन्तः स्थापित) – धारा 143–क के प्रावधान प्रभाव में भविष्यलक्षी है और वहीं आलम्ब लिया जा सकता है, जहाँ अन्तःस्थापन के पश्चात् धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया था।	**55**	**68**
Sections 138 and 147 – Whether dishonour of cheque issued in pursuance of a compromise arrived at Lok Adalat would constitute offence u/s 138 of the Act of 1881? Held, Yes.		
धाराएं 138 एवं 147 – क्या लोक अदालत में हुए समझौते के अनुसरण में जारी किए गए चेक का अनादरण 1881 के अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध का गठन करेगा? अभिनिर्धारित, हाँ।	**274***	**378**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
PARTNERSHIP ACT, 1932		
भागीदारी अधिनियम, 1932		
Sections 37 and 48 – Partnership firm – Distinction between "retirement of a partner" and "dissolution of a partnership firm".		
धाराएं 37 एवं 48 – भागीदारी फर्म – ''भागीदार के पदनिवृत्त होने'' और ''एक भागीदारी फर्म के विघटन'' के मध्य विभेद।	**325**	**449**
PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1947		
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947		
Sections 5 (1)(d) and 5(2) – See Sections 161, 166, 420, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 5 (1)(घ) एवं 5(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 161, 166, 420, 468 एवं 471।	**205**	**281**
PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988		
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988		
Sections 7, 12 and 13 – See Section 239 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 7, 12 एवं 13 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 239।	**152**	**211**
Sections 7, 13, 17, 19 and 20 – (i) Demand and acceptance of bribe money – Requirement of proof.		
(ii) Investigation – Not done by DSP – Effect.		
(iii) Sanction – An order of sanction should not be construed in a pedantic manner.		
(iv) Presumption – The standard required for rebutting presumption u/s 20 of the Act.		
धाराएं 7, 13, 17, 19 एवं 20 – (i) रिश्वत राशि की मांग एवं स्वीकृति – प्रमाण के लिए आवश्यकताएं।		
(ii) अन्वेषण – अधिनियम के अंतर्गत उप–पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्वेषण नहीं किया जाना – प्रभाव।		
(iii) मंजूरी – मंजूरी के किसी आदेश का अर्थ विशेषज्ञ के ढंग से नहीं लगाना चाहिए।		
(iv) उपधारणा – अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा खंडित करने के लिये आवश्यक मानक।	**222**	**313**
Sections 13 (1)(d) and 13 (2) r/w/s 19 – See Section 197 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 13 (1)(घ) एवं 13 (2) सहपठित धारा 19 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197।	**191**	**262**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 13 (2) r/w/s 13 (1)(e), 17 and 19 – (i) Acquisition of disproportionate assets – FIR – Scope and ambit of preliminary inquiry being a necessity before lodging an FIR would depend upon facts of each case – There is no set format or manner in which a preliminary inquiry is to be conducted.

(ii) Sanction for prosecution – Sanction can be produced by prosecution during course of trial and same may not be necessary after retirement of accused officer.

धाराएं 13 (2) सहपठित 13 (1)(ङ), 17 एवं 19 – (i) अनुपातहीन सम्पत्ति का अर्जन – प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किए जाने के पूर्व प्रारंभिक जांच की आवश्यकता की परिधि एवं सीमा प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर होती है – प्रारम्भिक जांच के संचालन हेतु कोई निश्चित प्रकार या प्रक्रिया नहीं है।

(ii) अभियोजन के लिये स्वीकृति – अभियोजन द्वारा विचारण के समय भी स्वीकृति प्रस्तुत की जा सकती है और यह अभियुक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति पश्चात् आवश्यक नहीं हो सकती है। **223** **317**

PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

Section 4 – Benefit of probation – After final disposal of main case, Court cannot grant benefit of probation to any accused and any order of probation cannot be granted without obtaining report of Probation Officer.

धारा 4 – परिवीक्षा का लाभ – मुख्य प्रकरण के अंतिम निपटारे के पश्चात् न्यायालय किसी भी अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दे सकता है तथा परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना परिवीक्षा का कोई भी आदेश स्वीकृत भी नहीं किया जा सकता है। **224** **319**

PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

Sections 3 and 9 – Marriage of a male aged between eighteen – twenty one years and an adult female – Male cannot be punished u/s 9 of the Act.

धाराएं 3 एवं 9 – 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की आयु के पुरूष तथा वयस्क महिला के मध्य विवाह – पुरूष को धारा 9 के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता। **225** **321**

PROPERTY LAW :

संपत्ति विधि :

– See Article 65 of the Limitation Act, 1963.

– देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 65। **56 (i)** **69**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

Section 4 – See Section 376(2)(1) (Prior to Amendment 2013) of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(1) (2013 के संशोधन से पूर्व)। **99*** **141**

Sections 5 (j) (ii) and 6 – (i) Age of prosecutrix, determination of.

(ii) Birth certificate – Proof.

(iii) Delay in FIR, effect of.

(iv) Presumption of culpable mental state – Must be rebutted beyond reasonable doubt.

धाराएं 5 (ञ)(ii) एवं 6 – (i) अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण।

(ii) जन्म प्रमाण पत्र – सबूत।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का प्रभाव।

(iv) दोषी मानसिक स्थिति की उपधारणा – युक्तियुक्त संदेह से परे खण्डित की जानी चाहिए। **57** **71**

Sections 5(m) and 6 – See Sections 302 and 376 (2) (i) (As inserted by Amendment Act of 2013) of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 5(ड) एवं 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 376 (2) (i) (2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अन्तः स्थापित)। **210** **287**

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

Sections 12, 18 and 27 – (i) Before issuing notice, the Court shall *prima facie* be satisfied that there have been instances of domestic violence.

(ii) The criminal case of domestic violence against other relatives of appellant cannot be continued as there are no specific allegations as to how they have caused the acts of domestic violence.

(iii) The petition under the Act can be filed in a court where the "person aggrieved" permanently or temporarily resides or carries on business or is employed.

धाराएं 12, 18 एवं 27 – (i) सूचना–पत्र जारी करने से पूर्व न्यायालय को प्रथम दृष्ट्या समाधान होना चाहिए कि घरेलू हिंसा कारित की गई है।

(ii) ऐसे कोई विनिर्दिष्ट आक्षेप आवेदक के रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं है कि उनके द्वारा किसी तरह की घरेलू हिंसा कारित की गई तब उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण जारी नहीं रखा जा सकता।

(iii) अधिनियम के अंतर्गत याचिका ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है जहां पीड़ित व्यक्ति स्थाई या अस्थाई रूप से रहता हो या व्यापार करता हो या नियोजन में हो। **275** **378**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958		
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958		
Sections 3 and 4 – See Section 360 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360।	**24**	**34**
REGISTRATION ACT, 1908		
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908		
Section 17 (1) – See Section 106 the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 17 (1) – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106।	**330**	**455**
Section 17(1)(b) – Admissibility of compulsorily registrable document.		
धारा 17 (1)(ख) – अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेज की ग्राह्यता।	**8* (iii)**	**9**
Sections 17 (1) (b) and (2) (vi) – Registration of compromise decree – when necessary.		
धाराएं 17 (1) (ख) एवं (2) (छः) – राजीनामा डिक्री का रजिस्ट्रीकरण कब आवश्यक है।	**170**	**234**
Section 47 – Registered document – Time of commencement of operation.		
धारा 47 – पंजीकृत दस्तावेज – संचालन प्रभावी होने का समय।	**110***	**151**
Section 49 – Unregistered sale deed – Declaration of title.		
धारा 49 – अपंजीकृत विक्रय विलेख – स्वत्व घोषणा।	**105***	**145**
REWA STATE LAND REVENUE AND TENANCY CODE, 1935		
रीवा राज्य भू–राजस्व तथा काश्तकारी संहिता, 1935		
Section 44 – See Section 158 (1)(d)(i) of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.); Sections 26 and 28 of the Vindhya Pradesh Abolition of Jagirs and Land Reforms Act, 1952; Section 58 of the Evidence Act, 1872 and Order 41 Rule 27 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 44 – देखें भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 158 (1)(क)(i); विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1952 की धाराएं 26 एवं 28; साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 27।	**317**	**437**
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989		
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989		
Section 3 – Offence registered under IPC as well as under the Act of 1989 – Investigated by an Officer below the rank of Deputy S.P., effect of?		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 3 – भा.दं.सं. के साथ–साथ 1989 के अधिनियम के अधीन अपराध दर्ज किया गया – अनुसंधान कार्यवाही उप–पुलिस अधीक्षक से न्यून पद के अधिकारी द्वारा की गई, प्रभाव?	**262**	**364**
Section 3 (2)(v) – See Sections 227 and 397 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 3 (2)(v) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 227 एवं 397।	**140**	**193**
Section 3 (2)(v) – The offence must have been committed against the person on the ground that such person is a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.		
धारा 3(2)(v) – अपराध किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	**93 (ii)**	**128**
Section 18A – See Section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 18क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	**144**	**197**
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) RULES, 1995		
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995		
Rule 7 – See Section 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
नियम 7 – देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3।	**262**	**364**
SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002		
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002		
Sections 13, 14 and 31 – District Magistrate cannot exercise the power conferred u/s 14 of the SARFAESI Act, 2002 for taking possession of any agricultural land as the provisions of the Act are not applicable in respect of any security interest created in agricultural land.		
धाराएं 13, 14 एवं 31 – सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान कृषि भूमि पर सृजित किसी सुरक्षा हित पर लागू नहीं होते हैं, इसलिये जिला मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किसी कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये नहीं कर सकता है।	**326**	**450**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
SERVICE LAW :		
सेवा विधि :		
– Effect of acquittal in criminal proceedings.		
– आपराधिक विचारण में दोषमुक्ति का प्रभाव।	**171**	**236**
SPECIFIC RELIEF ACT, 1963		
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963		
Section 5 – Recovery of possession of encroached land – Dispute as to boundaries – Encroachment of adjoining land – Matters to be established.		
धारा 5 – अतिक्रमित भूमि के कब्जे का प्रत्युद्धरण – सीमा का विवाद – संलग्न भूमि का अतिक्रमण – स्थापित की जाने वाली सामग्री।	**111 (i)***	**151**
Sections 10, 16(c) and 20 – Contract and Specific Relief: (i) Readiness and willingness of plaintiff buyer to perform his part of agreement for sale of immovable property.		
(ii) Suit for specific performance of agreement for sale, where agreement for sale has been cancelled by vendor.		
धाराएं 10, 16(ग) एवं 20 – संविदा एवं विनिर्दिष्ट अनुतोषः (i) अचल सम्पति के विक्रय की संविदा के अपने भाग के पालन हेतु वादी क्रेता का तैयार एवं रजामंद होना।		
(ii) विक्रय के लिये अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद, जहाँ विक्रेता द्वारा विक्रय के लिये अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है।	**58**	**77**
Sections 16 and 20 – Readiness and willingness – Delayed filing of suit and price of property – Consideration thereof.		
धाराएं 16 एवं 20 – तत्पर एवं इच्छुक – वाद का विलंब से दायर किया जाना एवं संपत्ति का मूल्य – विचारणीय पद।	**59**	**78**
Section 16 (c) – (i) Continuous readiness and willingness on the part of the plaintiff is a condition precedent to grant the relief of specific performance.		
(ii) Pleading and proof.		
धारा 16 (ग) – (i) वादी की ओर से लगातार तैयारी और रजामंदी विर्निदिष्ट अनुपालन की सहायता प्रदान करने की पुरोभाव्य शर्त है।		
(ii) अभिवचन और साबित किया जाना।	**172**	**237**
Section 16 (c) – See Section 149 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 16 (ग) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 149।	**234**	**330**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 16 (c) – Specific performance of contract – Readiness and willingness – Failure of plaintiffs to pay monthly installments of sale consideration, not collecting rent from tenants as stipulated in agreement, not paying municipal taxes etc. and not taking action for eviction of tenant – Effect.

धारा 16 (ग) – अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुपालन – तत्परता और इच्छुकता – विक्रय मूल्य की मासिक किस्तों का भुगतान करने में, अनुबंध के अनुसार किराएदारों से किराया वसूली करने में, नगरपालिक करों का भुगतान करने आदि में वादी की विफलता एवं किरायेदार के निष्कासन के लिए कार्रवाई नहीं करना – प्रभाव। **113 (ii) 153**

Section 16 (c) – Suit for specific performance of contract – Incorporation of averments as to readiness and willingness of plaintiff at the appeallate stage.

धारा 16 (ग) – संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद – अनुबंध के अपने भाग का अनुपालन करने के लिए वादी के तत्पर और इच्छुक होने के अभिवचन का अपीलीय स्तर पर समाविष्ट किया जाना। **112 152**

Sections 16 (c) and 20 (2)(c) – Suit for specific performance of contract – Readiness and willingness.

धाराएं 16 (ग) एवं 20 (2)(ग) – संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद – तत्परता एवं इच्छुकता। **114 155**

Sections 16 (c) and 28 – Specific performance of agreement – Grant of – Readiness and willingness – Principles summarised.

धाराएं 16 (ग) एवं 28 – अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन – का प्रदान किया जाना – तत्पर एवं इच्छुक – सिद्धांत संक्षिप्तिकृत। **60 80**

Section 20 – See Order 2 Rule 2(3) of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 20 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 2 नियम 2(3)। **182* 251**

Section 20 – See Order 1 Rule 10 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 20 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 10। **285 393**

Section 20 – Specific performance – Unless stipulations and terms of contract are certain and parties must have been *consensus ad idem*, specific performance cannot be ordered.

धारा 20 – विर्निदिष्ट अनुपालन – जब तक संविदा की शर्तें एवं पद निश्चित न हों एवं पक्षकारों के मध्य सहमति न हो, विर्निदिष्ट अनुपालन हेतु आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। **327 451**

Sections 31 and 38 – See Section 11 and Order 7 Rule 11(d) of the Civil Procedure Code, 1908 and also Article 59 of the Limitation Act, 1963.

धाराएं 31 एवं 38 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 एवं आदेश 7 नियम 11(डी) और परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 59। **3* 2**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 34 – Suit based on violation of condition of tenancy.		
धारा 34 – किरायेदारी की शर्तों के उल्लंघन पर आधारित वाद।	**173**	**238**
Section 34 – Suit for declaration; maintainability of – Absence of consequential relief – Effect of.		
धारा 34 – घोषणा के लिए वाद; पोषणीयता – पारिणामिक अनुतोष का अभाव – प्रभाव।	**115**	**157**
Sections 34, 38 and 39 – (i) Suit for injunction simpliciter. (ii) Civil Practice – Burden of proof.		
धाराएं 34, 38 एवं 39 – (i) मात्र व्यादेश के लिए वाद। (ii) सिविल प्रथा – सबूत का भार।	**328**	**452**
STAMP ACT, 1899		
स्टाम्प अधिनियम, 1899		
Section 35 – A person who after receiving full consideration, executed a sale deed, cannot seek impounding of agreement to sale in a later legal proceeding for non-payment of stamp duty.		
धारा 35 – एक व्यक्ति जो पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के बाद एक विक्रय विलेख निष्पादित करता है, पश्चात्वर्ती न्यायिक प्रक्रिया में स्टाम्प शुल्क के अभाव में उसी विक्रय विलेख से संबंधित पूर्व विक्रय अनुबंध को परिबद्ध करने की मांग नहीं कर सकता।	**226**	**322**
Section 35 – Objection relating to deficiency in stamp duty – Stage when to be decided?		
धारा 35 – स्टाम्प शुल्क में कमी की आपत्ति – किस प्रक्रम पर विनिश्चित की जानी चाहिए।	**276***	**380**
SUCCESSION ACT, 1925		
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Sections 74, 95 and 96 – The testator created an absolutely unfettered right in favour of his wife by virtue of the will and effect of clause as to sale and share of children.		
धाराएं 74, 95 एवं 96 – वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में आत्यांतिक अधिकार सृजित किया जाना और विक्रय तथा बच्चों के अंश से संबंधित खण्ड का प्रभाव।	**329**	**454**
Section 372 – Mere nomination does not create any right in favour of a wife who was not legally wedded.		
धारा 372 – एक पत्नी जो कि विधिक रूप से विवाहित नहीं थी, के पक्ष में मात्र नामनिर्देशन कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है।	**150 (ii)**	**210**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

Section 24 (2) – Sale of land involved in acquisition proceedings after issuance of notification u/s 4 of the Land Acquisition Act, 1894 – Validity and effect of.

धारा 24 (2) – अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के उपरांत अधिग्रहण की कार्यवाही के अध्यधीन सम्पत्ति का विक्रय – वैधता एवं प्रभाव। **227** **322**

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

Sections 3 and 123 – See Section 68 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 3 एवं 123 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68। **174** **239**

Sections 5 and 108 – (i) Concept of "unearned increase" – Explained.

(ii) Construction of document – Transfer by auction – Sale deed cannot be read in divorce to the auction notice.

धाराएं 5 एवं 108 – (i) 'अनर्जित वृद्धि'' की अवधारणा – समझाई गई।

(ii) दस्तावेज का निर्वचन – नीलामी के माध्यम से अंतरण – विक्रय विलेख को नीलामी सूचना के विच्छेद में नहीं पढ़ा जा सकता है। **277** **381**

Section 10 – Restricted gift, validity.

धारा 10 – निर्बंधित दान, विधिमान्यता। **175** **241**

Section 54 – See Sections 74, 95 and 96 of the Succession Act, 1925.

धारा 54 – देखें उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराएं 74, 95 एवं 96। **329** **454**

Section 54 – Whether actual payment of entire sale consideration at the time of execution of sale deed is essential for completion of sale? Held, No .

धारा 54 – क्या विक्रय विलेख के निष्पादन के समय संपूर्ण विक्रय प्रतिफल का वास्तविक भुगतान विक्रय के पूरा होने के लिए आवश्यक है? अभिनिर्धारित, नहीं। **286 (vi)** **393**

Sections 58 (d), 60 and 62 – See Article 61 (a) of the Limitation Act, 1963.

धाराएं 58 (घ), 60 एवं 62 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 61 (क)। **176** **242**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 60 – Extinguishment of mortgage – By the Act of parties.		
धारा 60 – पक्षकारों के कृत्य के द्वारा बंधक का निर्वापन।	**177**	**244**
Section 58 (c) – Mortgage by conditional sale or sale with option to repurchase.		
धारा 58 (ग) – सशर्त विक्रय द्वारा बंधक अथवा पुनः क्रय करने की शर्त के साथ बंधक।	**116***	**157**
Section 106 – Lease deed – Whether clause in lease deed stipulating 10% increase in monthly rent each year will make the lease year to year or more than one year requiring compulsory registration?		
धारा 106 – पट्टा विलेख – क्या पट्टा विलेख में यह खण्ड कि मासिक किराए में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी, पट्टे को वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक का बना देगा, जिसका पंजीयन अनिवार्य है?	**330**	**455**
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967		
विधि विरूद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967		
Sections 38 and 39 – Association with terrorist organisation with intention to further its activities punishable u/s 38 and garnering support for the terrorist organisation punishable u/s 39 – Scope and field of operation of these two sections.		
धाराएं 38 एवं 39 – आतंकी संगठन के साथ उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आशय से संबद्धता धारा 38 के अंतर्गत दण्डनीय है और आतंकी संगठन के लिए समर्थन प्राप्त करना धारा 39 के अंतर्गत दण्डनीय है – इन दोनों धाराओं का कार्यक्षेत्र तथा विस्तार।	**117**	**158**
VINDHYA PRADESH ABOLITION OF JAGIRS AND LAND REFORMS ACT, 1952		
विंध्य प्रदेश जागीर उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1952		
Sections 26 and 28 – See Section 158 (1)(d)(i) of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.); Section 44 of the Rewa State Land Revenue and Tenancy Code, 1935 ; Section 58 of the Evidence Act, 1872 and Order 41 Rule 27 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 26 एवं 28 – देखें भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 158 (1)(क)(i); रीवा राज्य भू–राजस्व तथा काश्तकारी संहिता, 1935 की धारा 44; साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 27।	**317**	**437**

PART – II A
(GUIDELINES)

1.	Guidelines for Special Courts trying cases under the Prevention of Corruption Act, 1988.	245
2.	Guidelines issued by Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh to be followed while deciding bail applications.	324
3.	बलात्संग एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के मामलों से संबंधित दिशा–निर्देश।	81
4	भरण–पोषण के मामलों से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश।	457

PART – III
(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1.	Notification dated 09.08.1996 of Department of Law and Legislative Affairs, Government of Madhya Pradesh, specifying the Court of Session as Human Rights Court.	3
2.	Notification dated 07.10.2017 of Home Department, Government of Madhya Pradesh, conferring the powers of Arrest, Investigation and Prosecution of Persons before any Special Court to all Officers of the rank of Police Inspector.	4
3.	Notification dated 08.12.2017 of Department of Law and Legislative Affairs, Government of Madhya Pradesh, specifying the Court of Session as a Special Court for Trial of Offences under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.	4
4.	Memorandum dated 20.12.2017 of High Court of M.P. regarding payment of travelling allowance to Government employee called as witnesses.	21
5.	Order dated 26.09.2018 of the High Court of Madhya Pradesh, designating Grievance Redressal Officer under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.	5
6.	Notification dated 16.11.2018 regarding amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961.	5
7.	Notification dated 16.11.2018 regarding amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal).	6
8.	Notification dated 14.12.2019 of Ministry of Home Affairs regarding the date of enforcement of the Arms (Amendment) Act, 2019	1
9.	Notification dated 10.01.2020 of Ministry of Social Justice and Empowerment regarding date of enforcement of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.	22
10.	Notification dated 21.02.2020 regarding Amendments in the Madhya Pradesh Arbitration Rules, 1997.	9

11.	Notification dated 10.04.2020 of Department of Public Health & Family Welfare, Government of Madhya Pradesh amending the Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020.	20
12.	Notification dated 26.06.2020 of Home Department, Government of Madhya Pradesh, regarding supply of copy of Police report alongwith annexed documents to the person/victim, who lodged FIR.	22
13.	Notification dated 14.09.2020 of the High Court of the Madhya Pradesh specifying Court which may dispose of urgent application when the court of Special Sessions Judge specified under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act is vacant	26
14.	Notification dated 22.09.2020 of Department of Revenue, Ministry of Finance authorising Officer of and above the rank of inspector of the National Investigation Agency to exercise the power and perform duties specified in section 53(1) of the NDPS Act, 1985.	25
15.	Notification regarding Criminal Law Amendment Ordinance, 1944	1
16.	Notification regarding date of enforcement of certain provisions of the Consumer Protection Act, 2019.	23
17.	सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों को शासकीय गवाह के रूप में आहूत किये जाने पर टी.ए./डी.ए. प्रदाय करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का परिपत्र दिनांक 06.10.2015।	21
18.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49(1) के प्रावधानों के अंतर्गत ''सुरक्षित स्थान'' घोषित करने संबंधी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 29.03.2016।	3
19.	समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट, 1949 की धारा 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकर प्रदत्त किये संबंधी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 07.03.2020।	7
20.	मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत, नोवल कोरोना (COVID-19) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित करने संबंधी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 18.03.2020।	8
21.	थाना प्रभारी (सब इंस्पेक्टर के पद से अन्यून) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कारित किये गये अपराधों के संबंध में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने संबंधी गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश दिनांक 23.04.2020।	20

PART – IV
(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1.	Madhya Pradesh Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020	9
2.	Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020	11
3.	The Arms (Amendment) Act, 2019	1
4.	The District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing and Audio-Visual Electronic Linkage Rules, 2020	37
5.	The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020	5
6.	The Madhya Pradesh Moneylenders (Amendment) Act, 2020	35

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
A. Mahalakshmi v. Bala Venkatram (dead) through L.Rs. and anr.	(2020) 2 SCC 531	178	247
Aarifaben Yunusbhai Patel and ors.v. Mukul Thakorebhai Amin and ors.	AIR 2020 SC 2344	318	440
Afjal Khan v. State of M.P.	2019 CriLJ 5003 (DB)	210	287
Amar Singh v. Kamla @ Sapna Panthi and ors.	2019 (3) MPLJ 200 (DB)	17	24
Amir Hamza Shaikh and ors. v. State of Maharashtra and anr.	AIR 2019 SC 3721	22	32
Anand Ramachandra Chougule v. Sidarai Laxman Chougala and ors.	AIR 2019 SC 3871	*86	116
Anil Karma and anr.v. State of M.P. and ors.	2020 (3) MPLJ 634 (DB)	326	450
Anil Kumar Sharma v. State of M.P.	2019 (3) MPLJ 177 (DB)	*32	40
Anokhilal v. State of M.P.	2020 (1) Crimes 303 (SC) (Three-Judge Bench)	187	257
ANSS Rajashekar v. Augustus Jeba Ananth	2020 (1) MPLJ 300 (SC) (Three-Judge Bench)	168	232
Anu Bhanvara Etc. v. IFFCO Tokio General Insurance Company Limited and ors.	AIR 2019 SC 3934	*107	146
APS Forex Services Pvt. Ltd. v. Shakti International Fashion Linkers and ors.	AIR 2020 SC 945	169	233
Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal and ors.	(2020) 7 SCC 1 (Three-Judge Bench)	*304	419
Arshnoor Singh v. Harpal Kaur and ors.	AIR 2019 SC 3098	35	43
Arun Kumar v. Anita Mishra and ors.	AIR 2019 SC 5745	*274	378
Arvind Singh v. State of Maharashtra	AIR 2020 SC 2451 (Three-Judge Bench)	306	423
Ashok Kumar Kalra v. Wing Cdr. Surendra Agnihotri and ors.	(2020) 2 SCC 394 (Three-Judge Bench)	185	254
Ashok Kumar Mehra and anr. v. State of Punjab etc.	2019 (4) Crimes 332 (SC)	155	215
Atma Ram v. Charanjit Singh	(2020) 3 SCC 311	234	330
Awadhesh Kumar v. State of U.P. and anr.	2019 (4) Crimes 219 (SC) (Three-Judge Bench)	211	292
Bachan Singh and ors.v. Rajveer Singh Yadav and ors.	2020 ACJ 1836	320	443
Badri Prasad Jharia v. Vatsalya Jharia	2020 CriLJ 3025	308	427
Badrilal (deceased) through L.Rs. Nirmala and ors. v. Akash and anr.	2019 (3) MPLJ 738	13	15
Baiju Kumar Soni and anr. v. State of Jharkhand	2019 (4) Crimes 455 (SC)	153	212

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Bajranglal (dead) through L.Rs. Draupadi and ors. v. Gajanand and anr.	2019 (3) MPLJ 614	7	7
Ballu Khan alias Ballu Kha alias Jahoor Shah v. State of M.P.	2019 CriLJ 4579	*74	98
Balvir Singh and ors. v. State of M.P.	2019 CriLJ 4100 (SC)	94	131
Balwan Singh v. State of Chhattisgarh and anr.	(2019) 7 SCC 781 (Three-Judge Bench)	82	109
Balwant Singh (D) through L.Rs. Gurbinder Singh v. State of Haryana and ors. etc.	AIR 2019 SC 1325	*103	143
BGS SGS SOMA JV v. NHPC Limited	(2020) 4 SCC 234	229	326
Bhagirath v. State of M.P.	ILR (2020) MP 210	*292	402
Bhagwan v. State of Maharashtra through Secretary Home, Mumbai, Maharashtra	(2019) 8 SCC 95	*95	135
Bhagwat Sharan (Dead) through L.Rs. v. Purushottam and ors.	(2020) 6 SCC 387	307	424
Bharat Sanchar Nigam Limited and ors. v. Pramod V. Sawant and anr.	AIR 2019 SC 3929	*21	32
Bondar v. Mishribai and ors.	2020 (1) MPLJ 571	124	167
Brijesh Kumar and anr. v. Shardabai (Dead) by L.Rs. and ors.	(2019) 9 SCC 369	104	144
C.S. Venkatesh v. A.S.C. Murthy (D) by L.Rs. and ors.	AIR 2020 SC 930	172	237
Canara Bank v. United India Insurance Company Limited and ors.	(2020) 3 SCC 455	246	340
Central Bureau of Investigation v. Ramendu Chattopadhyay	2019 (4) Crimes 295 (SC)	195	268
Central Bureau of Investigation v. Sakru Mahagu Binjewar and ors. etc.	AIR 2019 SC 3550 (Three-Judge Bench)	37	47
Chameli Devi and ors. v. Jivrail Mian and ors.	2019 ACJ 3011 (SC)	163	224
Chellappa v. State through The Inspector of Police	(2020) 5 SCC 160 (Three-Judge Bench)	311	429
Chhota Ahirwar v. State of M.P.	AIR 2020 SC 1150	261	363
Cobra CIPL v. Chief Project Manager	2020 (2) MPLJ 71	228	325
D. Devaraja v. Owais Sabeer Hussain	(2020) 7 SCC 695	296	408
Dahiben v. Arvindbhai Kalyanji Bhanusali (Gajra) Dead through L.Rs. and ors.	(2020) 7 SCC 366	286	393
Deep Narayan Chourasia v. State of Bihar	AIR 2019 SC 1148	79	105
Deepak alias Nanhu Kirar v. State of M.P.	2020 CriLJ 2076 (DB)	263	366

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Delhi Development Authority v. Karamdeep Finance and Investment (India) Private Limited and ors.	(2020) 4 SCC 136	277	381
Desh Raj v. Balkishan (Dead) through proposed L.Rs. MS Rohini	(2020) 2 SCC 708 (Three-Judge Bench)	*238	335
Dev Karan alias Lambu v. State of Haryana	AIR 2019 SC 3705	38	48
Dharmendra Raghuwanshi v. Radha Goyal and ors.	AIR 2020 MP 113	285	393
Dineshchandra Sharma (Deceased) through L.Rs. and ors. v. Rana Dharampal Singh and ors.	AIR 2020 MP 54	244	338
Dr. Kailashchandra v. Damodar (deceased) through Legal Heirs Smt. Reva Devi and ors.	2020 (2) MPLJ 40	232	329
Dr. Nallapareddy Sridhar Reddy v. The State of Andhra Pradesh and ors.	2020 (1) Crimes 198 (SC)	247	342
Dr. S. Kumar and ors. v. S. Ramalingam	AIR 2019 SC 3654	*29	38
Dr. Swapan Kumar Banerjee v. State of West Bengal and anr.	2019 (2) ANJ (SC) (Suppl.) 97	16	20
Executive Engineer, Nimna Dudhna Project, Selu, District Parbhani, Maharashtra v. State of Maharashtra and ors.	(2020) 3 SCC 255	266	371
Fahad Ahmed and ors. v. State of M.P.	M.Cr.C. No. 13259 of 2020, dated 12.05.2020	143	196
Firm Rajasthan Udyog and ors. v. Hindustan Engineering and Industries Limited	(2020) 6 SCC 660	*281	387
G.J. Raja v. Tejraj Surana	AIR 2019 SC 3817	55	68
Gajendra Singh v. State of M.P.	2020 CriLJ 3188 (M.P.)	314	434
Ganpati Babju Alamwar (D) by L.Rs. Ramlu and ors. v. Digambarrao Venkatrao Bhadke and ors.	AIR 2019 SC 4292	*116	157
Geetabhai and ors. v. State of M.P.	2019 CriLJ 4560 (M.P.) (DB)	*97	137
Girish Singh v. State of Uttarakhand	2019 AIR SC 4529	87	117
Govindbhai Chhotabhai Patel and ors. v. Patel Ramanbhai Mathurbhai	AIR 2019 SC 4822	*85	115
Gowramma and anr. v. Kalingappa (D) represented by L.Rs. and ors.	2019 (4) MPLJ 585 (SC)	177	244
Gudiya and ors. v. Govind Sharma and ors.	2020 ACJ 1569	268	372
Gurjit Singh v. State of Punjab	AIR 2020 SC 1785	258	360
Gurmail Chand v. State of Punjab	AIR 2020 SC 2161	324	448

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Gurmit Singh Bhatia v. Kiran Kant Robinson and ors.	AIR 2019 SC 3577	5	4
Gurshinder Singh v. Shriram General Insurance Co. Ltd. and anr.	2020 ACJ 1029 (SC) (Three-Judge Bench)	*272	376
Guru Nanak Industries, Faridabad and anr. v. Amar Singh (Dead) through L.Rs.	AIR 2020 SC 2484 (Three-Judge Bench)	325	449
Hardas Khamsingh Tadvi v. State of M.P.	2019 CriLJ 4075 (M.P.) (DB)	96	135
Hardev Singh v. Harpreet Kaur and ors.	AIR 2020 SC 37	225	321
Harishchandra v. Vijaykumar and ors.	2020 (1) MPLJ 393	176	242
Hemant Uday v. State of M.P. and anr.	2019 (3) MPLJ 131	*25	36
Hira Singh and anr. v. Union of India and anr.	AIR 2020 SC 3255 (Three-Judge Bench)	323	447
In Re : Assessment of the Criminal Justice System in response to Sexual Offences	2020 (1) Crimes 69 (SC) (Three-Judge Bench)	213	294
Indel Singh v. State of M.P.	2020 CriLJ 462 (DB)	136	182
Ishwarilal Yadav and anr. v. State of Chhatisgarh	(2019) 10 SCC 423 (Three-Judge Bench)	147	202
Jagat Bandhu v. Vijay Kaushal and ors.	2020 (2) MPLJ 353	*242	337
Jagat Narayan Sharma and anr. v. Mithleshi and ors.	2020 ACJ 1300	231	328
Jagbir Singh v. State (N.C.T. of Delhi)	AIR 2019 SC 4321	83	111
Jagdish Chandra Gupta v. Madanlal and ors.	2019 (3) MPLJ 353	10	13
Jagdish Prasad Patel (Dead) through L.Rs. and anr. v. Shivnath and ors.	ILR (2020) MP 43 (SC)	317	437
Jagjeet Singh Lyallpuri (dead) through L.Rs. and ors. v. Unitop Apartments and Builders Limited	(2020) 2 SCC 279 (Three-Judge Bench)	179	248
Jagmail Singh and anr. v. Karamjit Singh and ors.	(2020) 5 SCC 178	303	417
Jamil Khan and ors. v. State of M.P. and ors.	2019 (4) MPLJ 156	63	86
Jatinder Kumar v. State of Haryana	2020 (1) Crimes 1 (SC)	209	285
Javed Abdul Rajjaq Shaikh v. State of Maharashtra	2019 (4) Crimes 198 (SC)	198	275
Joginder Singh and anr. v. ICICI Lombard General Ins. Co. Ltd.	2019 ACJ 2783 (SC)	165	227
K. Lubna and ors. v. Beevi and ors.	(2020) 2 SCC 524	180	249
Kajal v. Jagdish Chand and ors.	AIR 2020 SC 776	164	224

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Kalindi Damodar Garde (D) by L.Rs. v. Manohar Laxman Kulkarni and ors. etc.	AIR 2020 SC 810	151	211
Kalu alias Laxminarayan v. State of M.P.	2019 (4) Crimes 194 (SC)	206	282
Kaluram v. Sitaram and ors.	2020 (1) MPLJ 411	128	171
Kanhaiyalal and anr. v. Rameshwar s/o Hardev and ors.	AIR 2020 MP 7	129	173
Kapoori and ors. v. State of M.P. and ors.	2020 (2) MPLJ 261	*243	337
Karnataka Power Transmission Corporation Limited represented by Managing Director (Administration and HR) v. C. Nagaraju and anr.	(2019) 10 SCC 367	171	236
Kashmira Devi v. State of Uttarakhand and ors.	2020 (1) Crimes 144 (SC)	264	368
Kastur Chand Jain (since dead) through L.Rs. Ashish Jain v. Keshri Singh	2020 (3) MPLJ 414	305	422
Kathi David Raju v. State of Andhra Pradesh and anr.	(2019) 7 SCC 769	15	19
Khuman Singh v. State of M.P.	AIR 2019 SC 4030	93	128
Kirit v. Smt. Sawarna	2019 CriLJ 3219	68	93
Kooli Saseendran and ors. v. State of Kerala etc.	AIR 2020 SC 1729	*251	350
Krishnamurthy S. Setlur (Dead) by L.Rs. v. O.V. Narasimha Setty (Dead) by L.Rs.	(2019) 9 SCC 488	56	69
Krishnaveni Rai v. Pankaj Rai and anr.	AIR 2020 SC 1156	260	362
Ku. Jhalak v. Rahul (deceased) through Smt. Seema	2020 (1) MPLJ 600	203	279
Kunjan Sadana and anr. v. Mahesh Kumar and ors.	2020 ACJ 812 (SC)	*270	374
Lakhanlal @ Lakhan Singh v. State of M.P.	2019 (3) Crimes 95 (SC)	24	34
Lakhi Ram Takbi v. State of Sikkim	2019 CriLJ 2667	57	71
Leeladevi and ors. v. Taradevi Farkya (deceased) through L.Rs. Satyanarayan and ors.	2020 (1) MPLJ 436	174	239
Life Insurance Corporation of India v. Basantilal Baraia and ors.	2020 (1) MPLJ 373	173	238
Lokpal Singh and anr. v. Matre and ors.	2019 (3) MPLJ 330	48	63
M.E. Shivalingamurthy v. Central Bureau of Investigation Bengaluru	2020 (1) Crimes 125 (SC)	139	191
M.S. Bhati v. National Insurance Co. Ltd.	2019 ACJ 2385	*108	147

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
M.S. Bhavani and anr. v. M.S. Raghu Nandan	AIR 2020 SC 1441	329	454
M/s Shree Daneshwari Traders v. Sanjay Jain and anr.	AIR 2019 SC 4003	109	148
M/s Sicagen India Ltd. v. Mahindra Vadineni and ors.	2019 (4) Crimes 360 (SC)	167	230
M/s. Fair Communication and Consultants and anr. v. Surendra Kerdile	AIR 2020 SC 1464	230	328
M/s. Z. Engineers Construction Pvt. Ltd. and anr. v. Bipin Bihari Behera and ors.	AIR 2020 SC 1140	*276	380
Madhya Pradesh Sadak Parivahan Nigam v. Pratima Sharma and ors.	2019 (3) MPLJ 651	*106	146
Mahadevappa v. State of Karnataka Rep. By Public Prosecutor	2019 (3) Crimes 29 (SC)	47	61
Mahanagar Telephone Nigam Ltd. v. Tata Communications Ltd.	AIR 2019 SC 1233	67	92
Maharaja Agrasen Hospital and ors. v. Master Rishabh Sharma and ors.	(2020) 6 SCC 501	302	415
Maharshi Vidya Mandir, Maihar v. Vijay Soni and ors.	2020 ACJ 607	161	222
Mahendra Kumar v. Lalchand and anr.	2019 (3) MPLJ 580	*8	9
Mahesh Kumar v. State of Haryana	(2019) 8 SCC 128	44	57
Mahindra and Mahindra Finance v. Rajkumari Bhadoria and ors.	AIR 2020 ACJ 728	*158	220
Mahipal v. Rajesh Kumar @ Polia and anr.	2019 (4) Crimes 321 (SC)	196	269
Maksud Sheikh Gaffur Sheikh v. State of Maharashtra	2020 CriLJ 3663 (FB)	299	411
Malarvizhi and ors. v. United India Insurance Co. Ltd. and anr.	2020 ACJ 526	218	308
Malikarjun and ors. v. State of Karnataka	(2019) 8 SCC 359	27	37
Malluru Mallappa (D) through L.Rs. v. Kuruvathappa and ors.	(2020) 4 SCC 313	*233	330
Mamta Kanoongo and ors. v. Dilip Agrawal and ors.	2020 (2) MPLJ 256	269	373
Man Khan v. Dr. Keshav Kishore and ors.	2019 (4) MPLJ 166	62	85
Manager, Cholamandalam MS General Ins. Co. Ltd. v. Ajay Choudhary and ors.	2020 ACJ 649	160	221
Managing Director, Chhattisgarh State Co-operative Bank Maryadit v. Zila Sahkari Kendriya Bank Maryadit and ors.	(2020) 6 SCC 411	*316	436

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Mangayakarasi v. M. Yuvaraj	AIR 2020 SC 1198	309	428
Mani Pushpak Joshi v. State of Uttarakhand and anr.	(2019) 9 SCC 805	*78	105
Manish Tiwari and ors. v. Deepak Chotrani and ors.	2020 (2) MPLJ 612	*241	336
Mankastu Impex Private Limited v. Airvisual Limited	AIR 2020 SC 1297 (Three-Judge Bench)	278	385
Manoharan v. State, By Inspector of Police, Variety Hall Police Station, Coimbatore	(2019) 7 SCC 716 (Three-Judge Bench)	39	49
Manoj Suryavanshi v. State of Chhattisgarh	(2020) 4 SCC 451 (Three-Judge Bench)	313	432
Mastram v. Karelal through L.Rs.	2019 (3) MPLJ 688	*4	3
Mauji Ram v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2019) 8 SCC 17	26	36
Mayank N Shah v. State of Gujarat and anr.	2020 (1) Crimes 53 (SC) (Three-Judge Bench)	205	281
Meena alias Munni and ors. v. State of M.P. and ors.	2020 (1) MPLJ 91 (DB)	120	160
Meera and ors. v. Har Prasad and ors.	2020 (2) MPLJ 297	*271	375
Mehboob-Ur-Rehman (Dead) through L.Rs. v. Ahsanul Ghani	AIR 2019 SC 1178	112	152
MMTC Ltd. v. M/s Vedanta Ltd.	AIR 2019 SC 1168	*61	85
Mohammade Yusuf and ors. v. Rajkumar and ors.	AIR 2020 SC 796	170	234
Mohammed Fasrin v. State represented by the Intelligence Officer	(2019) 8 SCC 811	*84	114
Mohammed Siddique and anr. v. National Insurance Company Limited and ors.	(2020) 3 SCC 57	219	309
Mohar Singh v. Gajenda Singh	2020 (3) MPLJ 411	282	388
Mohd. Anwar v. State (NCT of Delhi)	(2020) 7 SCC 391 (Three-Judge Bench)	312	430
Mohd. Younus Ali Tarafdar v. State of West Bengal	(2020) 3 SCC 747	*256	358
Mohinder Kaur v. Sant Paul Singh	(2019) 9 SCC 358	58	77
Mustak alias Kanio Ahmed Shaikh v. State of Gujarat	(2020) 7 SCC 237	315	435
Myakala Dharmarajam and ors. v. State of Telangana and anr.	(2020) 2 SCC 743	253	351
N. Mohan v. R. Madhu	AIR 2020 SC 41 (Three-Judge Bench)	181	249

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Nandu @ Gandharva Singh v. Ratiram Yadav and ors.	2019 (3) MPLJ 296	6	5
Narmada Prasad v. Bedilal Burman	2020 (1) MPLJ 217	122	165
National Insurance Co. Ltd. v. Dilip Kumar Jain and ors.	2020 ACJ 958	267	371
National Insurance Co. Ltd. v. Ram Murti Bai and ors.	2020 ACJ 594	159	220
National Insurance Company Limited v. Satish Kumar Verma and anr.	(2019) 8 SCC 660	51	66
Nawab v. State of Uttarakhand	(2020) 2 SCC 736	154	214
New India Assurance Co. Ltd. v. Ramkumar Sahu and ors.	2019 ACJ 2270	*52	67
Nusli Neville Wadia v. Ivory Properties and ors.	(2020) 6 SCC 557 (Three-Judge Bench)	288	397
Om Prakash and anr. v. Amar Singh and anr.	(2019) 10 SCC 136	186	256
Ombir Singh v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2020) 6 SCC 378 (Three-Judge Bench)	*294	407
Omprakash Bhargava v. Hotam Singh Kushwah	2019 CriLJ 4131	*73	97
P. Gopalkrishnan @ Dileep v. State of Kerala and anr.	2020 (1) Crimes 21 (SC)	215	300
Padam Chand Jain and ors. v. Mahaveer Prasad Jain	2020 (2) MPLJ 287	237	334
Padum Kumar v. State of Uttar Pradesh	(2020) 3 SCC 35	*201	277
Parenteral Drugs (India) Limited v. Jagdish Mangal HUF and ors.	AIR 2020 MP 91	290	400
Parsuram v. State of M.P.	(2019) 8 SCC 382	81	108
Patel Engineering Ltd. v. North Eastern Electric Power Corporation Ltd.	(2020) 7 SCC 167 (Three-Judge Bench)	279	386
Pattu Rajan v. The State of Tamil Nadu	2019 (3) Crimes 12 (SC)	18	25
Paul v. State of Kerala	(2020) 3 SCC 115	250	345
Paul v. T. Mohan and anr.	(2020) 5 SCC 138	*284	392
Pawan Kumar Gupta v. State of NCT of Delhi	2020 (1) Crimes 206 (SC) (Three-Judge Bench)	*265	370
Pradeep Ram v. State of Jharkhand and anr.	2019 (3) Crimes 110 (SC)	19	28
Pramod Kumar Jain and ors. v. Kusum Lashkari and ors.	2020 (2) MPLJ 357	245	339
Pratap Singh alias Pikki v. State of Uttarakhand	(2019) 7 SCC 424	42	55
Prathvi Raj Chauhan v. Union of India and ors.	AIR 2020 SC 1036 (Three-Judge Bench)	144	197

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Prayagnarayan Bansal v. Pavan Chandil	2020 (2) MPLJ 142	*240	336
Prem Chand Singh v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2020) 3 SCC 54	*249	344
Puneet Dalmia v. Central Bureau of Investigation, Hyderabad	2020 (1) Crimes 6 (SC)	192	265
Punit Agrawal v. Murarilal and ors.	2020 (3) MPLJ 368	287	396
Purnima Parekh v. Ashok Kumar Shrivastava and ors.	2020 (1) MPLJ 190	216	306
Purshottam Chopra and anr. v. State (Govt. of NCT Delhi)	AIR 2020 SC 476	146	199
Quality Agencies (M/s) v. The Commissioner, Customs and Central Excise	ILR (2020) MP 204 (DB)	289	398
R. Jaypal v. State of Tamil Nadu and anr.	(2019) 8 SCC 342	28	38
R. Lakshmikanthan v. Devaraji	(2019) 8 SCC 62	59	78
R. Srinivas Kumar v. R. Shametha	(2019) 9 SCC 409	34	42
Raja v. State by Inspector of Police	AIR 2020 SC 254	200	276
Raja alias Ayyappan v. State of Tamil Nadu	(2020) 5 SCC 118	301	412
Rajaram through L.Rs. Smt. Bhagwati Bai and ors. v. Laxman and ors.	AIR 2020 MP 9	149	209
Rajeev Singh v. Ram Singh and ors.	2020 (1) MPLJ 134	125	168
Rajender alias Rajesh alias Raju and ors. v. State (NCT of Delhi)	(2019) 10 SCC 623	76	100
Rajendra Singh and ors. v. National Insurance Co. Ltd. and ors.	(2020) 7 SCC 256	319	441
Rajesh Sharma v. State of M.P.	2019 CriLJ 4852	*72	96
Rajeshbhai Muljibhai Patel and ors. v. State of Gujarat and anr.	(2020) 3 SCC 794	257	359
Rakesh alias Tattu v. State of Madhya Pradesh and ors.	AIR 2020 SC 1929	*259	361
Rakesh Tiwari, Advocate v. Alok Pandey, C.J.M.	2019 (4) Crimes 365 (SC)	133	177
Ram Gopal v. Central Bureau of Investigation, Dehradun	AIR 2019 SC 3635	*92	128
Ramayan Prasad (since deceased) through L.Rs. Smt. Sumitra and ors. v. Indrakali and ors.	2019 (3) MPLJ 729	*105	145
Rambeti v Diksha and ors.	2020 (1) MPLJ 114	150	210
Rambhau Ganpati Nagpure v. Ganesh Nathuji Warbe and ors.	(2019) 9 SCC 202	*111	151
Ramchandra Dhakad and Karulal Dhakad v. Kailashchandra Upadhyay and Gram Panchayat, Lotkhedi	AIR 2020 (NOC) 712 MP	*280	387

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Ramesan (dead) L.Rs. Girija A v. The State of Kerala	2020 (1) Crimes 163 (SC)	*252	351
Ramesh Dasu Chauhan and anr. v. State of Maharashtra	(2019) 7 SCC 476	*43	57
Ramesh Kachhi v. State of M.P.	2020 CriLJ 333 (DB)	137	185
Ramkhiladi and anr. v. United India Insurance Co. Ltd. and anr.	2020 ACJ 627	162	223
Ramkrishan Sharma v. State of M.P. and ors.	2019 (3) MPLJ 474	*12	15
Ramswaroop Soni v. State of Madhya Pradesh and anr.	2019 CriLJ 4245 (SC)	69	94
Ranjit Kumar Haldar v. State of Sikkim	AIR 2019 SC 3542	*41	54
Ratnagiri Nagar Parishad v. Gangaram Narayan Ambekar and ors.	(2020) 7 SCC 275	328	452
Rathnamma and ors. v. Sujathamma and ors.	AIR 2020 SC 541	204	280
Ravi Setia v. Madan Lal and ors.	(2019) 9 SCC 381	60	80
Ravi v. State of Maharashtra	(2019) 9 SCC 622 (Three-Judge Bench)	148	207
Ravinder Kaur Grewal and ors. v. Manjit Kaur and ors.	AIR 2019 SC 3827 (Three-Judge Bench)	49	64
Ravinder Kaur v. Manjeet Singh (dead) through L.Rs.	(2019) 8 SCC 308	64	88
Ravishankar @ Baba Vishwakarma v. State of M.P.	(2019) 9 SCC 689 (Three-Judge Bench)	89	121
Rekha Murarka v. State of West Bengal and anr.	2019 CriLJ 3986	70	95
Ritesh Sinha v. State of Uttar Pradesh and anr.	AIR 2019 SC 3592	14	18
Rupa Roy v. New India Assurance Co. Ltd. and anr.	2019 ACJ 2382	*53	67
Saeeda Khatoon Arshi v. State of U.P. and anr.	2019 (4) Crimes 530 (SC)	193	266
Salim Khan alias Pappu Khan and anr. v. Shahjad Khan and anr.	2020 (1) MPLJ 355	126	169
Samsul Haque v. State of Assam	AIR 2019 SC 4163	75	98
Samta Naidu and anr. v. State of Madhya Pradesh and anr.	(2020) 5 SCC 378	293	403
Sangita Arya and ors v. Oriental Insurance Company Ltd. and ors.	(2020) 5 SCC 327 (Three-Judge Bench)	*321	445
Sanjay Bhargava @ Raju Bhargava v. Munni Devi and ors.	2019 (4) MPLJ 84	*110	151
Sanjay Rajak v. State of Bihar	AIR 2019 SC 3524	98	138

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Sanjeev Kapoor v. Chandana Kapoor and ors.	AIR 2020 SC 1064	135	182
Santosh Prasad alias Santosh Kumar v. State of Bihar	AIR 2020 SC 985	156	216
Sarnam Singh v. Gurmej Singh and ors.	2019 (4) MPLJ 75	115	157
Sarveshvar and ors. v. Sukhdev and ors.	2020 (2) MPLJ 557	236	333
Satinder Singh Bhasin v. Government of NCT of Delhi and ors.	2019 (4) Crimes 213 (SC)	138	190
Satish Kumar and anr. v. State of Himachal Pradesh and anr.	AIR 2020 SC 1729 (Three-Judge Bench)	*298	411
Satish Kumar Khandelwal v. Rajendra Jain and ors.	2020 (3) MPLJ 173	327	451
Satishkumar Nyalchand Shah v. State of Gujarat and ors.	AIR 2020 SC 1185	295	407
Shankarlal v. Mahila Ramdai and ors.	2020 (2) MPLJ 376	*235	333
Shanti Conductors Private Limited and ors. v. Assam State Electricity Board and ors.	(2020) 2 SCC 677 (Three-Judge Bench)	183	251
Sheela D/o Ramibai and anr. v. Bhagudibai and anr.	2019 (4) MPLJ 150	65	89
Shilaben Ashwinkumar Rana v. Bhavin K. Shah and anr.	2019 ACJ 3020 (SC)	132	177
Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi and anr.	2020(1) Crimes 109 (SC)	157	217
Shishupal Singh v. State of Uttar Pradesh and anr.	2019 CriLJ 4715 (SC)	*77	104
Shiv Kumar and anr. v. Union of India and ors.	(2019) 10 SCC 229 (Three-Judge Bench)	227	322
Shiv Prakash Mishra v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2019) 7 SCC 806	23	33
Shiv Shankar Prasad Singh v. State of Bihar	AIR 2019 SC 1190	*91	127
Shiv Singh v. Vandana	2019 (3) MPLJ 638	9	10
Shri Hanumant Dinkar Arjun v. Shri Suresh R. Andhare and anr.	2019 (4) Crimes 330 (SC)	197	274
Shri Revansiddeshwar Pattan Sahakari Bank Niyamit v. Taluka Tokrekoli (Ambiga Samaji C. Vikas Sangh India (Earlier Gangamath Sangha) and anr.	2019 (4) MPLJ 549 (SC)	119	160
Shri Uttam Chand (D) through L.Rs. v. Nathu Ram (D) through L.Rs. and ors.	AIR 2020 SC 461	*217	307
Shyamlal Devda and ors. v. Parimala	2020 CriLJ 2114	275	378
Siri Chand (Dead) through L.Rs. v. Surinder Singh	(2020) 6 SCC 288 (Three-Judge Bench)	330	455

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Smt. Madhu Rani v. State (Govt. of NCT of Delhi) and anr.	2020 CriLJ 551	*194	267
Smt. Reena Tuli v. Naveen Tuli	AIR 2019 MP 169	33	41
Smt. Sayna Bee v. Israr Ahmad	2019 CriLJ 3128	*100	141
Smt. Sunita Tokas and anr. v. New India Insurance Co. Ltd. and anr.	AIR 2019 SC 3921	50	65
South East Asia Marine Engineering and Constructions Limited (SEAMEC Limited) v. Oil India Limited	(2020) 5 SCC 164 (Three-Judge Bench)	291	401
Sri A.M.C.S. Swamy, ADE/DPE/Hyd (Central) v. Mehdi Agah Karbalai and anr.	AIR 2019 SC 3650	30	39
Sridhar and anr. v. N. Revanna and ors.	AIR 2020 SC 824	175	241
Srilekha Sentilkumar v. Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Chennai	2019 (4) Crimes 331 (SC)	152	211
State of Arunachal Pradesh v. Ramachandra Rabidas alias Ratan Rabidas and anr.	(2019) 10 SCC 75	166	229
State of Haryana v. Angoori Devi and anr.	AIR 2019 SC 3647	*101	142
State of Kerala etc. v. Rajesh etc.	2020 (1) Crimes 158 (SC)	255	357
State of M.P. v. Pakchi alias Virendra and Dharmendra	2019 CriLJ 4919 (DB)	*214	299
State of M.P. v. Yogeshnath alias Jogeshnath	2020 CriLJ 721 (DB)	*141	194
State of Madhya Pradesh and anr. v. Dungaji (dead) represented by L.Rs. and anr.	(2019) 7 SCC 465	*2	2
State of Madhya Pradesh and ors. v. Uday Singh and ors.	2019 (4) Crimes 420 (SC)	145	197
State of Madhya Pradesh v. Babbu Rathore and anr.	2020 (1) Crimes 210 (SC)	262	364
State of Madhya Pradesh v. Deepak	2020 CriLJ 638	140	193
State of Madhya Pradesh v. Killu @ Kailash and ors.	2020 (1) Crimes 47 (SC)	212	293
State of Madhya Pradesh v. Man Singh	2019 (4) Crimes 243 (SC)	224	319
State of Madhya Pradesh v. Suresh	AIR 2019 SC 1377	88	119
State of Madhya Pradesh v. Udham and ors.	(2019) 10 SCC 300 (Three-Judge Bench)	199	275
State of Punjab v. Baljinder Singh and anr.	(2019) 10 SCC 473 (Three-Judge Bench)	220	310
State of Rajasthan v. Mehram and ors.	AIR 2020 SC 2089	*297	410
State of Uttar Pradesh v. Ravindra @ Babloo and ors.	2020 (1) Crimes 57 (SC)	208	284

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
State of Uttarakhand v. Darshan Singh	2019 (4) Crimes 227 (SC)	190	261
State Represented by the Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Tamil Nadu v. J. Doraiswamy etc.	AIR 2019 SC 1518	*71	96
State v. Khimji Bhai Jadeja	2019 (3) Crimes 1 (Del.)	46	59
Station House Officer, CBI/ACB/Bangalore v. B.A. Srinivasan and anr.	2019 (4) Crimes 313 (SC) (Three-Judge Bench)	191	262
Subhash Sahebrao Deshmukh v. Satish Atmaram Talekar and ors.	(2020) 6 SCC 625	*300	412
Sudam alias Rahul Kaniram Jadhav v. State of Maharashtra	(2019) 9 SCC 388	40	51
Sudesh Kohli v. Chandarani Mishra and anr.	2020 (1) MPLJ 377	131	175
Sudhirdas v. United Church of D Canada India, Dhar Beneficiary and ors.	AIR 2019 MP 165	*3	2
Sugreev Kumar v. State of Punjab and ors.	2019 (4) Crimes 370 (SC)	142	195
Sukumaran v. State Represented by the Inspector of Police	AIR 2019 SC 1389	90	123
Sunita v. State of Haryana	AIR 2019 SC 3571	*31	40
Suraj Jagannath Jadhav v. State of Maharashtra	2019 (4) Crimes 575 (SC)	207	283
Surajbhan v. Ramnarayan through L.Rs. & ors.	2019 (3) MPLJ 495	1	1
Surendra Kumar Bhagwanlal Solanki and anr. v. Rameshchandra Bhagwanlal Solanki and anr.	AIR 2020 MP 42	184	253
Surinder Kaur (D) through L.Rs. Jasinderjit Singh (D) through L.Rs. v. Bahadur Singh (D) through L.Rs.	AIR 2019 SC 4194	114	155
Suryakant Baburao alias Ramrao Phad v. State of Maharashtra and ors.	AIR 2019 SC 3629	*36	46
Sushil Thomas Abraham v. Skyline Build Through its Partner and ors.	2019 (4) MPLJ 13	66	90
Sushila Aggarwal and ors. v. State (NCT of Delhi) and anr.	2020 (1) Crimes 225 (SC) (Constitution Bench)	254	352
Terai Tea Company Limited v. Kumkum Mittal and ors.	(2019) 10 SCC 142	226	322
Than Kunwar v. State of Haryana	(2020) 5 SCC 260	322	445
The State of Telangana v. Sri Managipet @ Mangipet Sarveshwar Reddy	2020 (1) Crimes 81 (SC)	223	317
Tilak Sahkari Grah Nirman Sanstha Maryadit v. Aqeel Ahmed and ors.	2020 (1) MPLJ 332	121	161
Trilochan Khora v. State of Orissa	2019 CriLJ 4988	189	260

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Triloki Nath Singh v. Anirudh Singh (dead) through L.Rs. and ors.	(2020) 6 SCC 629	283	388
U. C. Surendranath v. Mambally's Bakery	AIR 2019 SC 3799	11	14
Union of India and anr. v. Ankur Gupta and ors.	AIR 2019 SC 1316	*102	142
Union of India v. Yasmeen Mohammad Zahid alias Yasmeen	2019 CriLJ 4222 (SC)	117	158
Urmila Devi and ors. v. Branch Manager, National Insurance Co. Ltd. and anr.	2020 ACJ 771 (SC) (Three-Judge Bench)	273	376
Urvashi Aggarwal (Since deceased) through L.Rs. and anr. v. Kushagr Ansal (Successor in interest of erstwhile Defendant No.1 Mrs. Suraj Kumari) and ors.	AIR 2019 SC 1280	113	153
Ushadevi and anr. v. Cotton Corporation of India Ltd. and anr.	2020 (1) MPLJ 200	118	159
Uttam Ram v. Devinder Singh Hudan and anr.	2019 (4) Crimes 440 (SC)	221	311
Vallabh Electronics v. Branch Manager, United Bank of India	2020 (1) MPLJ 100	123	166
Varadarajan v. Kanakavalli and ors.	AIR 2020 SC 740	127	170
Varsha v. State of M.P.	2020 CriLJ 1944	248	343
VarunTalreja v. MuskanTalreja and anr.	2020 (3) MPLJ 460 (DB)	310	429
Vidyabai and ors. v. Laxmi Rajoriya and ors.	2020 (1) MPLJ 156	130	174
Vijay Gopala Lohar v. Pandurang Ramchandra Ghorpade and anr.	AIR 2019 SC 3272	*54	68
Vijay Trading and Transport Company v. Central Warehousing Corporation	(2020) 3 SCC 147 (Three-Judge Bench)	*188	260
Vimal v. State of Madhya Pradesh	2019 CriLJ 4785	*99	141
Vinod Kumar Garg v. State (Government of National Capital Territory of Delhi)	(2020) 2 SCC 88	222	313
Vinubhai Haribhai Malaviya and ors. v. State of Gujarat and anr.	2019 (4) Crimes 267 (SC) (Three-Judge Bench)	134	179
Vishnu Kumar Tiwari v. State of Uttar Pradesh through Secretary Home, Civil Secretariat Lucknow and anr.	AIR 2019 SC 3482	20	30
Vurimi Pullarao v. Vemari Vyankata Radharani Dhankoteshwarrao and anr.	AIR 2020 SC 395	*182	251
Wasim v. State of NCT of Delhi	2019 (3) Crimes 157 (SC)	*45	59
X v. State of Chhattisgarh	2019 CriLJ 4017 (DB)	*80	107
Yogendra Sangle v. State of M.P.	2020 (1) MPLJ 84	202	278
Zamindar Dharmik and Shekshnik Nyas, Indore v. Siddhanath (deceased) through his L.Rs.	2020 (2) MPLJ 100	*239	335